



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2012/पौष 27, 1933

No. 13]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

अंतिम जांच परिणाम

**विषय :** अमरीका तथा जापान के मूल के या वहां से निर्यातित एनीलिन के आयातों के बारे में निर्णायक समीक्षा जांच।

सं. 15/19/2010-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए :

### पृष्ठभूमि

1. यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने अमरीका तथा जापान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित एनीलिन के आरोपित पाटन के बारे में 20 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. 15/19/2010-डी जी ए डी के तहत निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू की। मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अमरीका तथा जापान से एनीलिन के आयातों पर 31-8-2000 की अधिसूचना सं. 33/1/99-डी जी ए डी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी और केन्द्र सरकार ने 6 अक्टूबर, 2000 की सी.शु. अधिसूचना सं. 128/2000-सी.शु. के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना कि संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा इस बात की समीक्षा हेतु उचित रहेगी कि क्या यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 के (5) के उपबंध के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है और समीक्षा के उपरांत प्राधिकारी ने 5 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 15/2/2005-डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए। 2006 की अधिसूचना सं. 58/2006-सी. शु. के तहत संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर निश्चयत्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया।

3. और यतः नियमों में प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की समय-समय पर समीक्षा करने की अपेक्षा की गई है और यदि वह उसे प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे शुल्क को निरंतर जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी उसे वापस लेने के बारे में केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं।

4. उपर्युक्त उपबंध के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को अमरीका तथा जापान के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की द्वितीय निर्णयिक समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दायर एक आवेदन मिला और उसमें संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि करने/उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया गया था।

### प्रक्रिया

5. इस जांच के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू पी सं. 2006 की 16893 में पारित आदेश के अनुरूप इस बात की जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के (5) के अनुसार निर्णयिक समीक्षा शुरू की। प्राधिकारी ने 20 दिसंबर, 2010 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया और अमरीका तथा जापान के मूल की या वहां से निर्यातित एनीलिन के आयातों के बारे में पाटनरोधी निर्णयिक समीक्षा जांच शुरू की।
- ii. प्राधिकारी को मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टलाइजर्स कंपनी लि. द्वारा दायर एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें अमरीका तथा जापान के मूल की या वहां से निर्यातित एनीलिन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया था।
- iii. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों को भेजी और नियम 6 (2) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर संगत सूचना प्रदान करने तथा लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	देश
1	मै. सुमितोमो कैमिकल कंपनी लिमिटेड	जापान
2	मै. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड	जापान
3	मै. बेर कार्पोरेशन	अमरीका
4	मै. बी ए एस एफ कारपोरेशन	अमरीका
5	मै. डूपोट	अमरीका

iv. संबद्ध देशों के इनमें से किसी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया ।

v. नियम 5 (5) के अनुसार नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

vi. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, उपभोक्ताओं, औद्योगिक प्रयोक्ताओं को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें नियम 6 (2) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में तथा ढंग से संगत सूचना प्रदान करने एवं लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी ।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई	2	टबीर कैमिकल्स लि., अहमदाबाद
3	एल्बीनेट्स एलाइड कैमिकल्स प्रा. लि., बदलापुर	4	एल्फा डाइज एंड कैमिकल्स, अहमदाबाद
5	एनीरोक्स पिग्मेंट्स लि., कोलकाता	6	एशियाटिक कलर कैम इंडस्ट्रीज अहमदाबाद
7	अतुल लि., हैदराबाद	8	बायर इंडिया लिमिटेड, मुंबई
9	बैक (इंडिया) लि. पुणे	10	भगेरिया डाइकैम लि., मुंबई
11	डायमन्ड डाइमन्ड, मुंबई	12	गणेश कैमिकल्स इंडस्ट्रीज मुंबई
13	हिन्दुस्तान लिंक्स एंड रेजिन लि. वारी	14	इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एंड कैमिकल लि. मुंबई
15	इंटरनेशनल डाइस्टफ इंडस्ट्रीज, वडोदरा	16	जय कैमिकल इंडस्ट्रीज लि. अमहादाबाद
17	मंगलम छाग्स एंड आर्गेनिक्स मुंबई	18	मेघमानी डाइज एंड इंडस्ट्रीज अहमदाबाद
19	मैट्रोकैम इंडस्ट्रीज लि., अहमदाबाद	20	मै. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज, मुंबई

21	नूतन डाइकैम, सूरत	22	पंडासरा इंडस्ट्रीज लि., पंडासरा
23	रवि डाइवेयर कं. लि., मुंबई	24	रूप डाई एंड इंटरमीडिएट्स, सुरेन्द्रनगर
25	सोनकमल इंटरप्राइजेज प्रा. लि., मुंबई	26	विपुल डाईकैम लि., मुंबई
27	स्केनेवेटडी बैक (इंडिया) लि., मुंबई		

vii. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दायर किया ।

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	मे. एन ओ सी आई एल लि.
2	रवि डाइवेयर कं. लि.
3	कच्छ कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
4	इंडस्ट्रियल सोलोवेट्स एंड कैमिकल्स प्रा. लि..
5	मे. डाई स्ट्राफिंग मैन्यु. एसोसिएशन ऑफ इंडिया

viii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कोलकाता से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के द्वारे प्रदान करे । डी जी सी आई एंड एस से सूचना मिल गई थी ।

ix. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियां उपलब्ध कराई । अगोपनीय आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।

x. यह जांच अक्टूबर, 2009 से सितंबर, 2010 की अवधि अर्थात् जांच अवधि के लिए की गई थी । तथापि, क्षति जांच वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 की अवधि और जांच अवधि के लिए की गई थी ।

xi. प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के अनुसार मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हेतु 4 अगस्त, 2011 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों/सूचना के बारे में खंडनात्मक तर्क/उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर समुचित विचार किया है ।

xii. जांच की कार्रवाई के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तकाँ और प्रदत्त सूचना/साक्ष्य पर प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा और वर्तमान जांच में संगत पाई गई सीमा तक समुचित विचार किया गया है ।

xiii. जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी ने स्वयं को प्रस्तुत सूचना की पर्याप्तता और सत्यता के बारे में संतुष्ट किया। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया।

xiv. नियम 6 (7) के अनुसार, प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा।

xv. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया जा रहा है और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में विचार किया जाएगा।

xvi. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

xviii. \*\*\* यह चिन्ह इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाठनरोधी नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है।

### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :—

- वर्तमान समीक्षा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। मूल जांच, प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद एनीलिन है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में निर्धारित किया है।
- एनीलिन एक पारदर्शी, तैलीय तरल और एक प्राथमिक अमीन यौगिक है। नए सिरे से निथारण किए जाने पर इसका रंग हल्का पीला तरल हो जाता है। इसका रंग तब गाढ़ा होता है जब उसे प्रकाश या वायु में लाया जाता है। एनीलिन औषधि, भेषज, रंजक तथा रंजक मध्यवर्तियों जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए

एक मूलभूत कार्बनिक रसायन है। एनीलिन का उपयोग रबड़ रसायन, विस्फोटक, रेजिन आदि जैसे कुछ अन्य उद्योगों में भी किया जाता है।

iii. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सी. शु. उप शीर्ष सं. 2921.41 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है। इस सूचना का मिलान प्रतिवादी विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना के साथ किया गया है।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित एनीलिन भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी (विश्व भर के अधिकांश उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली) कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का अदल-बदल कर उपयोग किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित एनीलिन समान वस्तु है।

v. वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच पूर्ववर्ती जांचों में की है जिन पर भरोसा किया गया है।

### आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, उत्पादक/निर्यातक तथा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तु का तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो विचाराधीन उत्पाद से हर तरह से समनुरूप या समान है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जिसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती-जुलती हैं।

9. विचाराधीन उत्पाद एनीलिन है जो एक पारदर्शी, तैलीय तरल तथा एक प्राथमिक अमीन यौगिक है जिसका उपयोग औषध, भेषज, रंजक और रंजक मध्यवर्तियों जैसे उद्योगों में किया जाता है। एनीलिन का उपयोग रबड़ रसायन, विस्फोटक, रेजिन आदि जैसे कुछ अन्य उद्योगों में भी किया जाता है। एनीलिन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के

अध्याय 29 के सी. शु. उप शीर्ष सं. 2921.41 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एनीलिन में ऐसी विशेषताएँ हैं जो संबद्ध देशों से आयातित एनीलिन से मिलती-जुलती हैं। उपर्युक्त के मददेनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित एनीलिन नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तुएँ हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एनीलिन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सी. शु. उप शीर्ष सं. 2921.41 के अंतर्गत वर्गीकृत है और यह कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

### घरेलू उद्योग

#### घरेलू उद्योग के विचार

11. जांच की शुरूआत और घरेलू उद्योग के आधार के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जी एन एफ सी) द्वारा दायर अनुरोध के आधार पर शुरू की गई है। एक अन्य प्रमुख उत्पादक हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल लि. (एच ओ सी एल) ने भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत सूचना प्रस्तुत की है। इसका अगोपनीय रूपांतरण भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।
- ii. यह याचिका गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। जांच शुरूआत के बाद प्राधिकारी ने एच ओ सी एल सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को पत्र भेजे और एच ओ सी एल ने तदनुसार लागत एवं क्षति संबंधी सूचना दायर की। अतः यह कहना गलत है कि घरेलू उद्योग के घटकों में परिवर्तन करने का यह प्रयास है। एच ओ सी एल पूर्ववर्ती जांचों में भी घरेलू उद्योग का भाग था।
- iii. क्षति निर्धारण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए “समग्र घरेलू उद्योग” पर विचार करना अपेक्षित होता है।
- iv. ऐसा तब होता है जब समग्र घरेलू उत्पादकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं होती है और जब समग्र घरेलू उत्पादक निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नहीं होते हैं। तब निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन घरेलू उत्पादकों पर कानूनन विचार करने की अनुमति है जिनका सामूहिक उत्पादन पात्र भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता

है। अतः ऐसी स्थिति में जब एच ओ सी एल ने सूचना उपलब्ध कराई है तो उसके आंकड़ों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

v. किसी भी कंपनी ने असहयोग नहीं किया है और न ही उन्होंने प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना को रोका है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को जी एन एफ सी तथा एच ओ सी एल को घरेलू उद्योग के दायरे में मानना चाहिए।

vi. जहां तक याचिका में अपर्याप्त आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा अलग जांच अवधि पर विचार करने का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि याचिका निश्चित अवधि के लिए आंकड़ों के साथ दायर की गई थी जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अलग अवधि के साथ जांच शुरू की जिस पर घरेलू उद्योग का कोई नियंत्रण नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए कोई विधिक आधार नहीं है कि याचिका में दिए गए आंकड़े और प्राधिकारी द्वारा विचारित अवधि एक समान होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि जांच प्राधिकारियों के पास जांच की शुरूआत से पूर्व उक्त अवधि के लिए याचिका होनी चाहिए।

vii. इस याचिका में अवधि और विस्तृत जांच हेतु प्राधिकारी द्वारा 'की गई जांच दो अलग—अलग मापदंड हैं जिन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी विधिक या वास्तविक आधार के बिना मिश्रित किया जा रहा है। कोई भी विरोधी पक्षकार जांच अवधि की शुरूआत द्वारा उन्हें हुए पूर्वाग्रह को न्यायोचित ठहराने में सक्षम नहीं है। जहां तक अद्यतित याचिका का संबंध है, उसको दायर करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि याचिका को जांच शुरू करने के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व दायर करना अपेक्षित होता है।

viii. जांच की शुरूआत और अंतिम निर्धारण के समय सूचना और साक्ष्य की गुणवत्ता नितांत अलग है जैसा कि डब्ल्यू टी ओ में ग्वाटेमाला से संबंधित मामले में निर्धारित किया है। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि साक्ष्य की गुणवत्ता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है। घरेलू उद्योग से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उचित रूप से उचित सूचना से अधिक कोई सूचना प्रदान करे।

ix. नोसिल ने प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है तथा अन्य के अनुरोधों में उत्तर में निहित सूचना का उचित और सार्थक अगोपनीय सारांश नहीं है।

x. हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है। नोसिल ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। डाई स्टफ मैन्यु. एसो. ने उसके सदस्यों पर इसके प्रभाव और उनके हितों की पुष्टि करते हुए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा, उसके सदस्यों का कोई व्यौरा नहीं दिया गया है और उसके सदस्यों द्वारा किए गए आयातों, खरीद, कीमत आदि के बारे में अन्य मात्रात्मक सूचना नहीं दी गई है।

## नियर्तक/उत्पादक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. वर्तमान जांच में किसी भी आयातक ने उत्तर नहीं दिया है। तथापि, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आधार के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां दायर की हैं।

- i. याचिका और जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में जांच अवधि तथा क्षति अवधि में अंतर है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है जिसके आधार पर उसने जांच अवधि में परिवर्तन किया है।
- ii. सार्वजनिक फाइल में आवेदन अलग जांच अवधि (अप्रैल 2009 से जून, 2010) के लिए किया गया था और क्षति विश्लेषण वर्ष 2006–07 से किया गया था जबकि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के अनुसार जांच अवधि अक्टूबर, 09 से सितंबर, 2010 की है और क्षति विश्लेषण वर्ष 2007–08 और उससे आगे किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण है इसलिए याचिका से इतर याचिका से भिन्न जांच अवधि लेने के बारे में निर्णय उस स्थिति में विशेष हो जाता है जब वर्तमान मामले के समान उसी दिन एक समान अंतर जांच की जा रही हो।
- iv. आवेदन का अगोपनीय रूपांतरण 30 दिसंबर, 2010 को दायर किया गया था। तथापि, बार-बार अनुरोध करने के बाद भी आयातक को आवेदन की प्रति 19 मई, 2011 को उपलब्ध कराई गई थी। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच अवधि के बारे में सूचना आवेदन में उपलब्ध नहीं थी। आयातक को अद्यतित सूचना 27 जुलाई को ही मिली थी।
- v. वस्ततः जांच की शुरूआत के बाद आवेदन का अगोपनीय रूपांतरण दायर करना कानूनन अनुमत नहीं है। इससे यह पता चलता है कि आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से पूर्ण तथा अद्यतित याचिका दायर नहीं की है।
- vi. याचिका का अगोपनीय रूपांतरण पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है और इससे उस पर टिप्पणी करने के हमारे अधिकार में गंभीर बाधा पहुंची है।
- vii. यह याचिका केवल गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर कंपनी लि. ने दायर की थी। बाद में इसने भागीदार कंपनियों का नाम बताए बिना समग्र घरेलू उद्योग के लिए क्षति संबंधी समेकित सूचना प्रदान की। सार्वजनिक फाइल में ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है। अतः याचिकाकर्ता के रूप में एच ओ सी एल ने कानून की अपेक्षा को पूरा नहीं किया है और इसलिए एच ओ सी एल के आंकड़ों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- viii. सुनवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि एच ओ सी एल ने आंकड़े प्रस्तुत करने अथवा सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने हेतु किसी परामर्शदाता के नाम से कोई प्राधिकार पत्र दायर नहीं किया है। परामर्शदाता

का यह उत्तर कि सुनवाई न किए जाने का मुददा तुच्छ है क्योंकि यह भागीदारों पर निर्भर है कि वे कढ़ाई से अनुपालन करने हेतु ऐसे किसी मामले की गभीरता के बारे में निर्णय लें। पाटनरोधी नियम के उल्लंघन हेतु परामर्शदाता ने इस बारे में जानबूझ कर चाल चली है कि क्या किसी कंपनी को घरेलू उद्योग का भाग माना जा सकता है।

- ix. जांच की शुरूआत के बाद घरेलू उद्योग के घटकों में परिवर्तन का प्रयास अनुचित है। इस बात का निषेध थाइलैंड, चीन, ताइपेई तथा नार्वे से कास्टिक सोडा के मामले में और सऊदी अरब, कोरिया गण, एवं अमरीका से कास्टिक सोडा की मध्यावधि समीक्षा में किया गया है। इसे ग्वाटेमाला से स्टील पाइप एवं ट्यूब पर मैक्सिको-पाटनरोधी शुल्क के मामले में भी बरकरार रखा गया है।
- x. जांच शुरूआत के बाद घरेलू उद्योग का निरंतर पूर्वानुमान और पुनर्गठन अनुमत्य नहीं है।
- xi. सार्वजनिक सुनवाई में याचिकाकर्ता का यह तर्क निराधार है कि घरेलू उद्योग को समग्र रूप में लिया जाना चाहिए ताकि उसमें शेष घरेलू उत्पादक शामिल हो सकें जबकि न्यायालय ने यह निर्णय निर्णय दिया है कि क्षतिरहित कीमत की गणना विचाराधीन उत्पाद हेतु समग्र घरेलू उद्योग के लिए की जानी चाहिए। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा उद्भूत ई सी बैडलिनन ने यह निर्णय दिया गया है कि जांचकर्ता प्राधिकारी क्षति निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग के नमूने पर ही विचार नहीं कर सकते। निर्दिष्ट प्राधिकारी कास्टिक सोडा के मामले में इस परंपरा से भटक गए हैं।
- xii. यूंकि एच ओ सी एल 5-6 माह की अवधि के लिए बंद रही थी इसलिए उस अवधि के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- xiii. याचिकाकर्ता ने संशोधित याचिका में क्षति के खतरे और पाटन के तर्काधार को अद्यतित नहीं किया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

- 13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह याचिका गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। जांच की शुरूआत के बाद चीन में संबंधित उत्पाद के अन्य उत्पादकों सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों को पत्र भेजे गए थे। एच ओ सी एल ने उत्पादक के रूप में जांच की शुरूआत का उत्तर दिया और लागत एवं क्षति संबंधी सूचना प्रदान की जिसका प्राधिकारी ने सत्यापन किया है।
- 14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि एच ओ सी एल 5-6 माह तक बंद रही और एच ओ सी एल को हुई क्षति के अन्य कारक हैं और प्रकीर्ति द्वारा एच ओ सी एल को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि एच ओ सी एल को वास्तव में बंद नहीं किया गया था बल्कि उसने अत्यधिक मालसूची के कारण अपना उत्पादन स्थगित किया था। एच ओ सी एल द्वारा उत्पादन स्थगित करने में कोई तकनीकी बाधा या कारण नहीं है। उत्पादन के स्थगन के समय कंपनी के पास बिक्री की पूर्ति हेतु पर्याप्त भंडार था। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हितबद्ध पक्षकार इस बारे में कोई उचित तर्क नहीं दे सके कि कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे से क्यों अलग रखा जाना चाहिए।

प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के दायरे से किसी उत्पादक को उसी स्थिति में अलग रखने का नियमों में प्रावधान है जब आयात अथवा आयातकों/निर्यातकों के साथ कोई संबंध सिद्ध होता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि जी ऐन एक सी तथा एच ओ सी एल का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है और वे नियमों के अर्थ के भीतर समग्र घरेलू उद्योग हैं।

याचिका और जांच शुरूआत संबंधी सूचना में विचारित जांच अवधि अलग है जिसका हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष दायर याचिका में जांच अवधि और विस्तृत जांच हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच अवधि एक ही होनी चाहिए। प्राधिकारी ने विस्तृत जांच हेतु अवधि पर विचार किया है। तदनुसार घरेलू उद्योग ने जांच शुरूआत के बाद संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए जिन्हें सार्वजनिक फाइल के जरिए हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया है।

यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने एक अन्य ऐसी जांच शुरू की है जिसमें जांच अवधि अलग है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है जिसमें अलग जांच में जांच अवधि समान होनी चाहिए।

प्राधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जांच अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़े सार्वजनिक फाइल के जरिए हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें उन पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

जहां तक एच ओ सी एल द्वारा सूचना प्रदान करने अथवा एच ओ सी एल की सूचना दायर करने हेतु प्राधिकार का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एच ओ सी एल द्वारा उक्त सूचना विधिवत् प्राधिकृत उसके काउसिल के जरिए दायर की गई थी। इसके अलावा, प्राधिकारी यह मानते हैं कि एच ओ सी एल के आंकड़ों को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस तथ्य कि एच ओ सी एल के निष्पादन पर अन्य कारकों के कारण प्रभाव पड़ा है का अर्थ यह नहीं है कि इस कंपनी को घरेलू उद्योग से अलग रखा जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसी स्थिति जिसमें घरेलू उद्योग के निष्पादन पर अन्य कारकों का प्रभाव पड़ा है, उसका स्वयं कानून में स्पष्ट समाधान है जिसके लिए प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पृथक रखे। इस प्रकार यदि एच ओ सी एल के अन्य कारकों से भी क्षति हुई है तो इस हेतु कंपनी को अलग रखना उचित होगा। इसके बजाए कंपनी को यह भी अपेक्षित है कि वह ऐसे अन्य कारकों हेतु एच ओ सी एल के निष्पादन का समायोजन करे। हितबद्ध पक्षकारों के दावे के प्रतिकूल जांच से यह पता चला है कि एच ओ सी एल के पास संयंत्र चलाने में कोई तकनीकी बाधा नहीं है।

**वस्तुतः** एच ओ सी एल ने वर्ष 1997-98 में 24128 मीट. का उत्पादन किया था। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जी एन एफ सी के साथ एच ओ सी एल के हाइड्रोजन या एनीलिन के उत्पादन लागत की तुलना करना इस वजह से उचित नहीं होगा कि जी एन एफ सी के पास अद्भुत हाइड्रोजन का उत्पादन नहीं होता है। हाइड्रोजन के लिए जी एन एफ सी की लागत में हाइड्रोजन की उत्पादन लागत प्रदर्शित नहीं होती है। जी एन एफ सी द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन अपशिष्ट गैस से किया जाता है और वह केवल हाइड्रोजन की लागत के अवसर लागत वसूलता है। आंकड़ों के आधार पर जी एन एफ सी द्वारा दावा किए गए एकल उत्पादन लागत से यह पता चलता है कि हाइड्रोजन की वास्तविक उत्पादन लागत इस समय वसूली गई राशि से बहुत अधिक होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने वस्तुतः यह तर्क दिया कि जी एन एफ सी की उत्पादन लागत में हाइड्रोजन की उचित उत्पादन लागत पर विचार कर न कि इस हेतु कंपनी द्वारा सूचित वास्तविक व्यय को देखते हुए उर्ध्वगामी संशोधन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियमों में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण भी अपेक्षित है और इसलिए घरेलू उद्योग के संघटकों का अलग-अलग निर्धारण उचित नहीं होगा। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निष्पादन और खासकर जी एन एफ सी और एच ओ सी एल, दोनों के लिए कीमत मापदंडों के बारे में प्रवृत्ति एक समान एक समान रही है अर्थात् क्षति अवधि में उनकी लाभप्रदता तथा नकद लाभ और निवेश पर आय में अत्यधिक गिरावट आई है।

20. यह तर्क दिया गया है कि जांच की शुरूआत के बाद घरेलू उद्योग के संघटकों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे दावे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके विपरीत प्राधिकारी के लिए कार्यवाही के प्रत्येक चरण पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र का निर्धारण करना अपेक्षित होता है। वस्तुतः जांच की शुरूआत का एक प्रयोजन समस्त संगत पक्षकारों से सूचना मांगना होता है और यदि एक या अधिक घरेलू उत्पादक जांच की शुरूआत के बाद प्राधिकारी को सूचना देते हैं तो प्राधिकारी के लिए क्षति निर्धारण हेतु ऐसी सूचना को शामिल करना अपेक्षित होता है। जहां तक इस बारे में कास्टिक सोडा के मामले के दिए गए हवाले का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि दोनों मामलों के तथ्य एक समान हैं और इस वजह से एच ओ सी एल को अलग रखना न्यायोचित है। इसके विपरीत ऐसे मामले भी हैं जिनमें जांच के दौरान अधिक उत्पादकों के लिए सूचना ली गई थी। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। अत्यधिक मालसूची के कारण कुछ अवधि के लिए एच ओ सी एल को बंद किए जाने मात्र का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके आंकड़ों को क्षति निर्धारण हेतु अलग रखा जाना चाहिए।

गोपनीयता  
घरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. निर्यात कीमत में से किए गए विभिन्न समायोजनों के दावे के कारणों को गोपनीय नहीं रखा गया है, याचिका में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस वजह से किए गए समायोजन याचिकाकर्ता की बाजार सूचना तथा पारंपरिक अनुमानों पर आधारित है।
- ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लागत सूचना गोपनीय प्रकृति की है और ऐसी सूचना की गोपनीयता की अनुमति प्राधिकारी ने भी दी है। निर्धारित प्रपत्र में भी ऐसी सूचना की गोपनीयता की अनुमति है।
- iii. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई बिक्री कीमत निवल बिक्री प्राप्ति नहीं है। सकल कीमत में विभिन्न समायोजन और छूट निहित है।

निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. गोपनीयता के संबंध में नियमों और कानून की प्रोज्यता याचिकाकर्ता पर भी लागू होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने उस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया है जिसका प्रकटन किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने भाड़े एवं अन्य ऊपरी व्यय जैसी सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया है जिसका प्रकटन किया जाना चाहिए था।
- ii. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बढ़ी हुई दरें लागू की हैं। कीमत कटौती का प्रकटन केवल अमरीका जैसे एक देश के संबंध में किया गया है जो ज़कारात्मक है। कम कीमत पर पर बिक्री का ब्यौरा नहीं दिया गया है। प्रपत्र क, ख, ग-1, ग-ii और घ में लागत सूचना को खाली छोड़ दिया गया है।
- iii. बिक्री कीमत की सूचना जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है उसे भी गोपनीय होने का दावा किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और गोपनीयता के दावे के बारे में संतुष्ट होने के उपरांत उसकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में आवेदन में किया गया गोपनीयता का दावा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप है। हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के असत्य दावे के कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए हैं। प्राधिकारी ने ऐसी सूचना के बारे में गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है जिसकी प्रकृति गोपनीय है क्योंकि

इसके प्रकटन से किसी याचिकाकर्ता को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा अथवा उसके प्रकटन से सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा ऐसे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा जिससे उक्त सूचना ली गई है। प्राधिकारी गोपनीय सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें।

### पाटन का निर्धारण - कार्यप्रणाली एवं सापदंड

#### सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

#### घरेलू उद्योग के विचार

24. पाटन के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया और सामान्य मूल्य का परिकलन किया।
- ii. वर्तमान जांच में याचिकाकर्ताओं ने अमरीका और जापान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में आवश्यक सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने हेतु समस्त उचित प्रयास करने के बावजूद संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमत के बारे में कोई साक्ष्य/सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। उपर्युक्त को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने परिकलित मूल्य पर विचार करते हुए संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- iii. निर्यात कीमत की गणना सामान्य मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर निर्यात कीमत की तुलना द्वारा सी आई एफ स्तर पर की जाती है। अतः निर्यात कीमत में समायोजन ऐसे विभिन्न व्यय हेतु किया गया है जो भारत को सामग्री के निर्यात हेतु निर्यातक द्वारा वहन की गई हो सकती है।
- iv. यथानिर्धारित संबद्ध वस्तु के बारे में संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और ज्यादा है। अतः भविष्य में पाटित कीमत पर आगे और निर्यात होने की प्रबल संभावना है।
- v. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि विरोधी पक्षकार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु संगत सूचना प्रदान करने का प्रतिनिधि नहीं है और उसे सामान्य मूल्य एवं उसके निर्धारण हेतु तर्क देने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती।
- vi. संबद्ध देशों (खासकर अमरीका) से एनीलिन का पाटन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी जारी है। संबद्ध देशों से सतत पाटन और बाजार में ऐसी पाटित सामग्री की

मौजूदगी से घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाइत आयातों के कुर्पभाव को दूर करते से बंचित हुआ है।

vii. मंदी के बाद की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है और अमरीका से कम आयात हुए हैं जो इस वजह से हुआ है कि अमरीका के अधिकांश उत्पादकों/निर्यातकों के पास यूरोपीय संघ में भी अपनी उत्पादन सुविधाएँ हैं। इसी वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाएंगा तो आयात पुनः अमरीका को होने लगेंगे। एकमात्र परिवर्ति लागत वृद्धिकारी भाड़ लागत में निहित है जो नगण्य है।

viii. इसके अलावा, केवल इस वजह से कि कोई पाटन नहीं हुआ है और इस प्रकार ऐसी किसी स्थिति में जिसमें संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर नहीं मिला है, यह संकेत नहीं देता है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृति होने और उसके जारी रहने की संभावना नहीं है।

### निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. वर्तमान जांच में किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। तथापि, अयातकों ने पाटन के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

- घरेलू उद्योग द्वारा की गई सामान्य मूल्य की गणना काफी अधिक है और वह किसी तथ्य या सिद्धांत पर आधारित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा कच्ची सामग्री के दिए गए कुछ और गलत हैं। याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से छेड़छाड़ की है।
- पाटन मार्जिन को बढ़ाने के लिए भाड़, ब्रीमा और अन्य प्रभारों की राशि अधिक बताई गई है।
- जांच अवधि के दौरान अमरीका से नगण्य और जापान से कोई आयात नहीं हुआ है। चीन, जनगण, कोरिया, गण, चीनी, ताइपेई और ब्राजील से फ्लेक्सीबल स्लैबस्टॉक पोलिओल के मामले में संबद्ध देशों से कोई आयात न होने के कारण शुल्क समाप्त कर दिया गया था।
- वर्तमान मामले में पाटन के दावे के समर्थन में याचिकाकर्ता ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने केवल अनुमान लगाए हैं।
- सामान्य मूल्य की गणना बेंजीन और विद्युत की लागत तथा जापान और अमरीका दोनों के लिए अमरीका में कीमत और लागत पर आधारित अन्य समायोजनों के अनुसार की गई है। सामान्य मूल्य की गणना हेतु याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई बेंजीन की दरें गलत हैं क्योंकि इन देशों की घरेलू बाजार की स्थितियों और कीमतों की जातकारी नहीं है।
- विद्युत, मूल्यहास और अन्य विनिर्माण व्यय से इतर उपयोगिताओं की लागत की गणना का कोई स्रोत नहीं दिया गया है। जापान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कोई भरोसेमंद स्रोत नहीं है। इसके अलावा, अमरीका में लागत के आधार पर परिकलित लागत स्वीकार्य नहीं है।

vii. यू एन कामट्रेउ से यह देखा जा सकता है कि जापान से काई निर्यात नहीं हुआ है। जापान के लिए निर्यात कीमत का परिकलन विधि विरुद्ध है। भारत में हुए सभी आयातों की भारित औसत कीमत लेकर जापान के लिए परिकलित निर्यात कीमत गलत और अनुचित है।

viii. जापान हेतु विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत की गणना के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली आधारहीन है क्योंकि भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के भारित औसत पर जापान से निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, निर्यात कीमत हेतु दावा किए गए समायोजनों का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं कराया गया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

26. धारा 9 (क) ग के अंतर्गत किसी वस्तु के बारे में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

27. जहां तक आवेदन में निर्धारित सामान्य मूल्य एवं पाटन मार्जिन के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिका में सामान्य मूल्य का दावा सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकारी को सुपुर्द एकमात्र सूचना है। प्राधिकारी ने ऐसे संबंधित विदेशी उत्पादकों से सूचना मांगी है जिन्होंने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से उत्तर नहीं दिया है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी प्रतिवादी आयातक / उपभोक्ता या अन्य हितबद्ध पक्षकार ने

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन या उसके किसी घटक के निर्धारण हेतु कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इन परिस्थितियों में जब निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है तो प्राधिकारी के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षित होता है। प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों का मात्र अनुपालन किया है और प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में खुद निर्धारण किया है।

### पाटन मार्जिन

#### सामान्य मूल्य

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरूआत का उत्तर नहीं दिया है और कोई सूचना/उत्तर नहीं दिया है। संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक ने वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत, तीसरे देशों को हुए निर्यातों के बारे में सूचना अथवा संबद्ध देशों में उत्पादन लागत और अन्य सूचना प्रश्नावली के अनुसार सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बेंजीन संबद्ध उत्पाद के उत्पादन हेतु एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। सामान्य मूल्य का निर्धारण आई सी आई एस एल ओ आर के अनुसार अमरीकी क्षेत्र में बेंजीन की कीमत और घरेलू उद्योग के खपत मानकों पर विचार करते हुए किया जाता है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि संबद्ध उत्पाद की कीमत में भारी अंतर है और संबद्ध देशों से निर्यातित सामग्री का जांच अवधि के सभी महीनों में निर्यात नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना मासिक आधार पर की जानी चाहिए। तदनुसार प्राधिकारी ने प्रत्येक माह के लिए पृथक् सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जिस माह में सामग्री का भारत को निर्यात किया गया है। तदनुसार भारित औसत सामान्य मूल्य \*\*\* अम. डा. प्रति किगा. निर्धारित किया जाता है।

#### निर्यात कीमत

29. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि किसी भी निर्यातक और उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है और कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अतः निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एस द्वारा प्रस्तुत आयात सूचना के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मई, 2010, जून, 2010 और सितंबर, 2010 से सामग्री का निर्यात किया गया है। प्राधिकारी ने माहवार पृथक् निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक कमीशन और अंतरदेशी भाड़े के लिए समायोजनों की अनुमति दी गई है। तदनुसार तीनों महीनों की भारित औसत निवल निर्यात कीमत \*\*\* अम. डा. प्रति किगा. बनती है।

30. जहां तक जापान का संबंध है, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु समस्त ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेंजीं। जापान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर और अनुरोध दायर नहीं किया। करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना ज़रूराने से

मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो कथनात्मक या नकारात्मक प्रारंभिक या अंतिम निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जाएंगे । चूंकि जांच अवधि के दौरान जापान से संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ था इसलिए वर्तमान पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

### पाटन मार्जिन की गणना

अम.डा. प्रति किग्रा.	अमरीका
सामान्य मूल्य (अम.डॉ.)	***
निर्यात कीमत (अम.डॉ.)	***
पाटन मार्जिन (अम.डॉ.)	***
पाटन मार्जिन%	5-10 %

### पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

31. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को निरंतर लागू रखना आवश्यक है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है :-

- मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन
- वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन - क्या जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात विद्यमान है । इस बात पर विचार किया गया और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया । जांच अवधि के दौरान जहां कोई निर्यात नहीं हुआ है वहां पाटन मार्जिन का निर्धारण मूल जांच में किए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है ।
- विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए ज्ञात विस्तार, भारत में प्रचलित कीमत, निर्यातों की वास्तविक और संभावित मात्रा, अन्य देशों को इन देशों की निर्यात कीमत पर विचार करते हुए मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान एवं संभावित क्षमताएं ।

32. इन कारकों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (क) अमरीका से निर्यात के मामले में पाटन मार्जिन सकारात्मक है ।
- (ख) अमरीका से निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम है ।
- (ग) अमरीका से निर्यातों का पहुंच मूल्य जांच अवधि में निर्धारित क्षति रहित कीमत तथा निवल बिकी प्राप्ति से काफी अधिक है ।

(घ) प्राधिकारी ने अमरीका से अन्य देशों को हुए निर्यातों के पहुंच मूल्य की तुलना भी की है और यह नोट करते हैं कि यह न केवल घरेलू उद्योग की निवल बिकी प्राप्ति एवं क्षति रहित कीमत से अधिक है अपितु भारत में सामान्य मूल्य की तुलना में भी अधिक है।

(ड.) प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्ति का निर्धारण करते समय संभावना की जांच को ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। इस संबंध में प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल इस वजह से कि अमरीका के निर्यातकों से कोई उत्तर नहीं मिला है, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से अमरीका से पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया था।

33. जहां तक जापान का संबंध है, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस आशय का सकारात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना है। जापान से तीसरे देशों को हुए निर्यातों के बारे में प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना से भी यह पता नहीं चलता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन एवं क्षति की संभावना नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध सूचना के अनुसार जापान में क्षमता 3,98,000 मी.ट. की है और वास्तविक उत्पादन 2,79,000 मी.ट. का हुआ है। परंतु बेशी क्षमता होने के बावजूद वर्ष 2010 में जापान से तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात या आयात नहीं हुआ है जिससे शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में विपर्यन की वास्तविक संभावना नहीं है।

### क्षति का निर्धारण तथा कारणात्मक संबंध की जांच

#### घरेलू उद्योग के विचार

34. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

- i. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात जारी है। वस्तुतः आयात मात्रा काफी अधिक रही है और बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है।
- ii. आयातों की पहुंच कीमत विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत से कम है।
- iii. घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में उतना सुधार नहीं कर सका जितना वह पाटित आयातों के अभाव में कर सकता था।
- iv. देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिकी और क्षमता उपयोग कम रहा है। संबद्ध वस्तु के सतत पाटन के कारण आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की बिकी में गिरावट आई है। भारत में संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग अपना उत्पादन और बिकी को ईंटतम बनाने तथा उसमें सुधार करने में समर्थ नहीं हुआ और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका।

v. यद्यपि, लाभप्रदता तथा निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है तथापि, ऐसा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण हुआ है। तथापि, वर्ष 2006-07 में घरेलू उद्योग के निष्पादन के साथ तुलना करने पर क्षति अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ, ब्याज पश्चात लाभ और ब्याज एवं मूल्यहास पूर्व लाभ कम रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ होता यदि बाजार में पाठित आयात न हुए होते। घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल बना हुआ है और इस प्रकार उसकी स्थिति नाजुक है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी संबद्ध देशों से पाठित आयातों की मात्रा काफी अधिक है।

vi. आधार वर्ष की तुलना में देश में मांग में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग विकी संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंच सकी अपितु जांच अवधि में उसमें गिरावट आई।

vii. क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा और परिणामतः संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है। संबद्ध देशों से आयातों में संभावित गिरावट और बाजार हिस्से में परिणामी गिरावट पाटनरोधी उपाय लागू होने के कारण आई है।

viii. एनीलिन एक “वस्तु उत्पाद” है। अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए अमरीका या जापान के उत्पादकों को यूरोप की कीमत के अनुरूप कीमतें रखनी होंगी जिनसे घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है।

ix. यदि एच ओ सी एल तथा जी एन एफ सी की क्षति संबंधी सूचना को अलग-अलग किया जाए तो यह पता चलेगा कि केवल जी एन एफ सी की लाभप्रदता 2006-07 में काफी अधिक और जांच अवधि में कम रही है। इसके अलावा, जांच अवधि की तुलना में 2006-07 में जी एन एफ सी द्वारा उत्पादित मंत्रा काफी अधिक रही थी। यदि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों से हुई थी तो जी एन एफ सी की मात्रा में गिरावट न आई होती और उसके लाभ में कमी न आई होती। जी एन एफ सी की क्षमता समूची अवधि में एक समान रही है। ऐसा मामला होने के कारण हितबद्ध पक्षकारों ने इस मुददे का समाधान नहीं किया है कि जी एन एफ सी का उत्पादन 7000 मी.ट. से घटकर लगभग 2600 मी.ट. क्यों हुआ और उसका घाटा इन वर्षों में बढ़कर लगभग दोगुना क्यों हो गया।

x. एच ओ सी एल के उत्पादन और विकी मात्रा में भारी गिरावट आई और उसके घाटे में अत्यधिक वृद्धि हुई। एच ओ सी एल की क्षमता समूची अवधि में एक समान रही है। ऐसा मामला होने के कारण हितबद्ध पक्षकारों ने इस मुददे का समाधान नहीं किया है कि एच ओ सी एल का उत्पादन 7000 मी.ट. से घटकर लगभग 2600 मी.ट. क्यों हुआ और उसका घाटा इन वर्षों में बढ़कर लगभग दोगुना क्यों हो गया।

xi. क्षति को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने के लिए एच ओ सी एल को शामिल करने का आरोप बेबुनियाद है क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए “घरेलू उद्योग” को हुई क्षति की जांच करना अपेक्षित होता है न कि घरेलू उद्योग के अलग-अलग घटकों को हुई क्षति की जांच करना।

xii. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क बुबुनियाद है कि याचिकाकर्ता की ब्याज लागत में सुधार हुआ है। प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत निर्धारित करते समय ब्याज लागत का समायोजन किया है।

xiii. जहां तक इस आरोप का संबंध है कि बेंजीन की कीमत में घट-बढ़ से एनीलिन का निष्पादन प्रभावित हुआ है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बेंजीन की कीमत में घटबढ़ न केवल भारत में अपितु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हुई है।

xiv. टी पी एम द्वारा एच ओ सी एल के प्रतिनिधित्व हेतु प्राधिकार पत्र प्राधिकारियों के पास दायर किया गया है औंश्र वह प्राधिकारी के रिकॉर्ड में है। इस वजह से कि प्राधिकार सार्वजनिक फाइल में नहीं है, यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि यह कंपनी किसी उचित प्राधिकार के बिना प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके अलावा, मौखिक सुनवाई के दौरान प्राधिकारी के प्रतिनिधित्व द्वारा यह पुष्टि नहीं की गई है कि प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से दिए गए विवरण को विरोधी पक्षकारों ने गलत समझा है।

xv. यह आरोप लगाया गया है कि एच ओ सी एल आबद्ध कच्ची सामग्री की उच्च लागत, उच्च श्रम लागत तथा निर्धारित लागत के कारण उत्पादन से दूर रहा है। इस संबंध में घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि अधिक या कम की तुलना एनीलिन के अन्य उत्पादक के संदर्भ में की जा रही है जो स्वयं गलत है।

xvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की तत्समय स्थिति पर विचार करना चाहिए न कि आदर्श स्थितियों के अंतर्गत। इसके अलावा, जैसा कि मौके पर सत्यापन के समय सूचित किया गया है, कंपनी हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास कर रही है। कंपनी ने अब प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है जैसा कि सत्यापन दौरे के समय देखा गया था। प्राकृतिक गैस के जरिए हाइड्रोजन का उत्पादन होने से कंपनी हेतु उत्पादन लागत में भारी गिरावट आई है।

xvii. जी एन एफ सी द्वारा कंपनी के अन्य संयंत्र से आबद्ध रूप में प्रमुख निविष्टि प्राप्त की जा रही है। इस आबद्ध निविष्टि की अंतरण कीमत न तो बाजार कीमत है और न ही पूर्ण लागत। इसके विपरीत एच ओ सी एल द्वारा हाइड्रोजन को छोड़कर सभी निविष्टियों की खरीद की जा रही है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति आबद्ध निविष्टियों के गलत मूल्यांकन के कारण विकृतिपूर्ण हो गई है। चूंकि जी एन एफ सी के मामले में आबद्ध निविष्टि अत्यंत कम मूल्य का उत्पाद है अन्यथा कंपनी के लिए उसकी अंतरण कीमत बाजार कीमत की तुलना में पूर्णतः अवास्तविक हो जाती। परिणामतः जी एन एफ सी के लागत आंकड़ों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत का उचित प्रदर्शन नहीं होता है।

xviii. वर्तमान मामले से यह स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो जाता है कि बाजार मूल्य से इतर मूल्य पर आबद्ध निविष्टि पर विचार करने से क्षति विश्लेषण में अत्यधिक विकृति आ सकती है और समेकित तथा असमेकित उत्पादकों के बीच भेदभाव हो सकता है जिससे ये उत्पादक खतरे में पड़ सकते हैं जो परस्पर व्यापारोन्मुखी रूप में एकीकृत नहीं हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें इस मामले में एनीलिन के अकेले उत्पादक और सामान्य तौर पर अन्य उत्पादक बाजार में विद्यमान नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य यह भी होगा कि कोई भी कंपनी एनीलिन का उत्पादन (और लाभ कमाना) तथा देश में अन्य उत्पादों का उत्पादन नहीं कर सकेगी जब तक कि उसके पास ऐसी आबद्ध निविष्टि के बाजार मूल्य से कम कीमत पर अपनी खुद की आबद्ध निविष्टि न हो।

xix. आबद्ध निविष्टियों की उच्च लागत, उच्च श्रम तथा निर्धारित लागत उत्पादन कम होने के कारण रही है जिसकी वजह भारत में एनीलिन का पाटन है। आयातों में लगातार वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग अधिक मालसूची से बचने के लिए अपना उत्पादन घटाने हेतु मजबूर हुआ है।

xx. विरोधी पक्षकारों ने जानबूझकर इन प्रमुख तथ्यों की अनदेखी की है कि बेंजीन की कीमत में काफी अधिक अंतर आया है जिसका परिणामी प्रभाव उत्पाद की लागत और कीमत पर पड़ा है। ऐसा मामला होने के कारण अकेली लागत और कीमत की तुलना समूचे वर्ष हेतु करना अमानक है। यदि इसकी तुलना माह-वार आधार पर की जाती है तो कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री समारात्मक होगी।

xxi. यदि अमरीका और जापान के संबंध में वर्तमान जांच है तो भी घरेलू उद्योग अन्य स्रोत अर्थात् ई यू से हुए पाटन के कारण नुकसान उठा रहा है और जांच चल रही है। ई यू से आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं जिससे क्षति हो रही है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण करना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली में उस स्थिति में संचयी निर्धारण का प्रावधान है जब निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह पता चलता है कि निर्दर्शनात्मक स्थितियों की पूर्ति हो रही है। अतः याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि एक साथ और अलग जांचों में पाटित स्रोतों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण न केवल वांछनीय है अपितु, जरूरी भी है।

35. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न मापदंडों से सामूहिक तथा संचयी रूप से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

#### निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

36. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :—

- i. जांच शुरूआत के 40 दिन बीत जाने के बाद एच ओ सी एल ने भाग लेने का अवसर गंवा दिया है। घरेलू उद्योग का यह एक अकुशल संघटक है जिसने घरेलू उद्योग को हुई क्षति को बढ़ावढ़ाकर किया है जिसका उल्लेख जी एन एफ सी के आंकड़ों में नहीं है। याचिकाकर्ता ने क्षति के आंकड़ों में भारी फेरबदल कर क्षति को बढ़ाने की कोशिश की है।
- ii. समूची क्षति अवधि के दौरान एच ओ सी एल का बाजार हिस्सा काफी कम 10 प्रतिशत रहा है जिसकी वजह आयातों को नहीं माना जा सकता।
- iii. दोनों भागीदार कंपनियों की प्रवृत्तियों की तुलना विरोधाभासी है। जी एन एफ सी ने 107 प्रतिशत क्षमता उपयोग किया जबकि एच ओ सी एल ने 22 प्रतिशत-27 प्रतिशत क्षमता उपयोग किया है।

iv. एच ओ सी एल आंतरिक कारणों से एक नियमित उत्पादक नहीं है। एच ओ सी एल ने वर्ष के दौरान विचाराधीन उत्पाद का टुकड़ों में उत्पादन किया है और अपना अधिक उत्पादन एक वर्ष में कुछ ही महीनों के दौरान अनियमित मात्रा और अवधि में किया गया था।

v. एच ओ सी एल की लाभप्रदता नकारात्मक है जबकि जी एफ सी की लाभप्रदता सकारात्मक है। एच ओ सी एल की बिकी मात्रा कुल घरेलू बिकी की मात्रा 13 प्रतिशत है। एच ओ सी एल को शामिल किए जाने से जी एफ सी का समूचा लाभ आमेलित हो गया है। इससे यह पता चलता है कि एच ओ सी एल के विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत अत्यधिक असामान्य है।

vi. हाल के वर्षों में एच ओ सी एल का क्षमता उपयोग कभी भी 35–40 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है। अतः एच ओ सी एल को शामिल किए जाने से क्षति की गलत स्थिति प्रदर्शित होगी। मामूली गिरावट आर्थिक मंदी और याचिकाकर्ता के पास अधिक स्टॉक के कारण आई है।

vii. एच ओ सी एल अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण लगातार प्रचालन नहीं कर रहा था। एच ओ सी एल ने इस तथ्य के बावजूद कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू बिकी कीमत से काफी अधिक है, घरेलू बाजार में बाजार हिस्सा नहीं बढ़ाया है। इससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि एच ओ सी एल को क्षति स्वतः हुई है।

viii. यदि पाटन घरेलू निष्पादन को प्रभावित करने का एकमात्र कारण है तो भागीदार कंपनियों के निष्पादन में प्रवृत्ति भी यही होनी चाहिए थी। एच ओ सी एल को हुआ भारी घाटा पाटन से इतर कारकों की वजह से हुआ है।

ix. याचिकाकर्ता ने क्षति विश्लेषण हेतु 2006–07 को आधार वर्ष के रूप में लेकर क्षति को बढ़ाने और सूचीबद्ध आंकड़ों में भारी परिवर्तन करने की कोशिश की है।

x. सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि में ऐसे पाटन से संबंधित मुद्दों के संदर्भ का स्पष्ट अभाव है जिससे एनीलिन के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा है।

xi. मात्रात्मक प्रभाव का निर्धारण करते समय आयात में वृद्धि पर गौर करना अपेक्षित होता है और वर्तमान मामले में जापान से कोई आयात नहीं हुआ है तथा अमरीका से हुए आयात में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। क्षति और पाटित आयातों के बीच को सह संबंध नहीं है।

xii. वर्ष 2009–10 में कोई आयात न होने के बावजूद घरेलू बिकी कीमत में गिरावट आई है। अतः यह बिकी लागत है जो कि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य जिससे घरेलू उद्योग की घरेलू बिकी कीमत पर प्रभाव पड़ा है।

xiii. इस मामले में कोई कीमत कटौती तथा कम कीमत पर कोई बिकी नहीं हुई है।

xiv. याचिकाकर्ता ने क्षतिरहित कीमत का कोई ब्यौरा नहीं दिया है।

xv. मांग में वृद्धि के बावजूद आयातों में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कोई गिरावट नहीं आई है।

xvi. निविष्टियों की आबद्ध उत्पादन की उच्च लागत, उच्च श्रम लागत, उच्च क्षमता उपयोग के कारण अधिक निर्धारित लागत, और संयंत्र पर लागत के अधिक प्रभाव के कारण विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं हुआ ।

xvii. वर्ष 2008–09 को छोड़कर बिकी मात्रा में वृद्धि हुई है जो संयंत्र बंद होने और आर्थिक मंदी के कारण क्षमता उपयोग में आई गिरावट के कारण हुआ है । बिकी में गिरावट केवल कम उत्पादन मूल्य के कारण आई है । क्षति अवधि के दौरान उत्पादन बिकी का अनुपात एक समान रहा है ।

xix. याचिकाकर्ता की वर्ष 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि लाभ को अधिकतम बनाने के लिए उत्पादन का समायोजन किया गया है और पाटन के कारण कोई घाटा नहीं हुआ है ।

xx. जी एन एफ सी ने व्यापारियों के जरिए प्रचालन किया और इसलिए विचारणीय वास्तविक कीमत जी एन एफ सी की कीमत से काफी अधिक है जिससे क्षति (यदि कोई हो) आगे और कम हो जाती है । इन व्यापारियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है ।

xxi. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के प्रचालनात्मक लाभ, पूंजी पर आय (एन एफ ए) में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

xxii. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से कोई आयात हुए बिना वर्ष 2009–10 में भी क्षति का दावा किया है । अतः उस समय हुई क्षति आरोपित आयातों के कारण नहीं हुई है अपितु अन्य कारकों की वजह से हुई है ।

xxiii. वर्ष 2007–08 से घरेलू उद्योग की ब्याज दरों में अचानक वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने कोई क्षमता विस्तार नहीं किया है इसलिए ब्याज व्यय के स्रोत का सत्यापन किया जाना चाहिए । पिछले कुछ वर्षों में पी बी आई टी, बिकी कीमत और बिकी मूल्य में वृद्धि हुई है, चारों वर्षों में कीमत कटौती नकारात्मक रही है जिससे यह पता चलता है कि ब्याज दर में वृद्धि घरेलू उद्योग को हुई अनुभूत हानि के कारणों में से एक कारण है ।

xxiv. घाटा अनुषंगी उत्पादों की खराब बिकी के कारण हुआ है जैसा कि 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जिससे एनीलिन हेतु अस्थिर बाजार स्थिति उत्पन्न हुई है ।

xxv. बैंजीन की कीमत से एनीलिन की कीमत में आयातों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ा है । क्षति अवधि में बैंजीन की कीमत अस्थिर रही है ।

xxvi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति और आरोपित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है । घरेलू उद्योग की नकारात्मक कीमत कटौती और उसे हुए भारी मुनाफे के साथ इतनी लंबी अवधि तक संबद्ध देशों से किसी अधिक मात्रा में आयात न होने से कारणात्मक संबंध से इंकार किया जाता है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने की संभावना भी नहीं है ।

xxvii. देशों का संचयन करने के लिए उचित समान परिस्थितियों और अवधि की मौजूदगी होनी चाहिए और ऐसे संचयन हेतु अनुरोध करने का संबद्ध पक्षकारों के पास कोई कारण नहीं

हो सकता और यह गलत तथ्य भी है। ऐसे कुछेक कारक हैं जो समानांतर जांच में विशिष्ट होते हैं अर्थात् (क) जांच की प्रकृति (ख) बाजारों में आपस में और संबद्ध देशों में आपस में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में (ग) जांच अवधि यद्यपि, अतिव्याप्ति होने की स्थिति में अलग-अलग कर दी गई हो।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

37. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के बारे में किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निर्णयिक जांच की है और वर्तमान निर्धारण किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :—

(क) जहां तक क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ एच ओ सी एल को शामिल किए जाने का संबंध है, इस स्थिति की जांच की गई है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह तथ्यतः गलत है कि एच ओ सी एल का क्षमता उपयोग हमेशा काफी कम रहा है। वस्तुतः एच ओ सी एल ने 1997-98 में लगभग 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग किया है। इसके बावजूद कंपनी को उस समय प्रचालानात्मक तथा तकनीकी स्थिति का सामना करना पड़ा और इस समय इसके क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह कहना गलत है कि एच ओ सी एल एनीलिन का नियमित उत्पादक नहीं है। कंपनी ने मालसूची में काफी अधिक वृद्धि होने पर ही एनीलिन का उत्पादन रोका है।

(ख) प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि जी एन एफ सी की क्षति संबंधी सूचना से यह पता चलता है कि कंपनी के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, कंपनी की लाभप्रदता उचित स्तर से कम है।

(ग) प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई आयात न होने के बावजूद वर्ष 2009-10 में क्षति के बारे में दिए गए तर्कों का जहां तक संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि इस अवधि में यूरोपीय संघ से उत्पाद का अत्यधिक आयात हुआ है जो कथित तौर पर पाटित कीमतों पर हुआ है और इस समय जांच चल रही है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मात्र इस वजह से कि वर्तमान निर्णयिक समीक्षा जांच जापान और अमरीका के संबंध में है, इसका तात्पर्य यह नहीं निकलता है कि यूरोपीय संघ से हुए पाटित आयातों के प्रभाव की खासकर उस स्थिति में पूर्णतः अनदेखी की जानी चाहिए जब घरेलू उद्योग के निष्पादन का निर्धारण किया जा रहा हो। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में यह भी तर्क दिया है कि नियमों में घरेलू उद्योग पर “पाटित आयातों” के परिणामी प्रभाव का निर्धारण करने का प्रावधान है। चूंकि यूरोपीय संघ से आयात कथित रूप से पाटित कीमत पर हुए हैं इसलिए घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव से समस्त पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चलेगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णयिक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी के लिए पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने के बारे में निर्धारण करना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस तर्क की भी जांच की है कि यूरोपीय संघ से निर्यात अमरीका से विपरित होकर शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में आ जाते हैं। प्राधिकारी ने इन अनुरोधों की जांच की है और यह पाया है कि ये मात्र आशंकाएं हैं। इस तथ्य से कि कुछ उत्पादकों के ई यू और अमरीका में संयंत्र हैं, उनके इस मामले की पुष्टि नहीं होती है कि ई

यू से होने वाले आयात अमरीका को कर दिए जाएंगे और भाड़े का प्रभाव अमरीका के मामले में अधिक होगा तथा अमरीका से संबद्ध वस्तु की कीमत हर हालत में अधिक रहेगी। घरेलू उद्योग ने अपने दावे के समर्थन में रिकॉर्ड में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया। अतः घरेलू उद्योग से किसी वास्तविक साक्ष्य के अभाव में तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध में कोई गुण नहीं पाते हैं।

(घ) जहां तक इन तर्कों का संबंध है कि याचिका में क्षति रहित कीमत या कम कीमत पर बिकी के बारे में कोई सूचना नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पर ऐसा कोई विधिक दायित्व नहीं है। वस्तुतः क्षति रहित कीमत या कम कीमत पर बिकी का निर्धारण निर्दिष्ट प्राधिकारी करता है। हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान प्रकटन विवरण के जरिए इस पर टिप्पणी करने का अवसर दिया जा रहा है।

(ड.) जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अतिभज्ञात अन्य कारकों से एच ओ सी एल की उत्पादन लागत अधिक होने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान प्रयोजन हेतु एच ओ सी एल की वास्तविक उत्पादन लागत नहीं ली गई है। वस्तुतः घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण एच ओ सी एल के 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए किया गया है ताकि अन्य कारकों से हुई किसी क्षति को समाप्त किया जा सके। अतः यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि एच ओ सी एल की उत्पादन लागत उत्पादन में घाटे और विभिन्न लागतों के उच्चतर प्रभाव के कारण अधिक हो सकती है। एच ओ सी एल तथा जी एन एफ सी के खपत संबंधी मानकों की तुलना से यह पता चलता है कि एच ओ सी एल की कच्ची सामग्री की खपत से संबंधित मानक जी एन एफ सी के मानकों से नितांत तुलनीय हैं।

(च) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने एच ओ सी एल की उत्पादन लागत और उसके द्वारा उत्पादन लागत में प्रभारित विभिन्न व्यय के दावे को स्वीकार नहीं किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की विस्तृत जांच की है और पर्याप्त जांच के बाद ही व्यय स्वीकार किए गए हैं।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क दिया गया है कि एच ओ सी एल नियमित रूप से उत्पादन नहीं करता है और कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने कंपनी के परिसरों और रिकॉर्डों का सत्यापन किया है। यह नोट किया गया है कि एनीलिन के उत्पादन में कोई तकनीकी बाधा नहीं है। कंपनी ने दावा किया कि एकमात्र बाधा बिकी की है क्योंकि ग्राहक पाटित सामग्री के बराबर कीमत पर मांग करते हैं। जब कभी कंपनी ने उत्पादन रोका तो प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उस समय मालसूची का स्तर काफी अधिक था। यह नोट किया जाता है कि अप्रैल, 2011 में मालसूची बढ़कर 1227 मीट. हो गई। कंपनी ने तब भी मई, 2011 में संबद्ध उत्पाद का उत्पादन किया और मालसूची का रखरखाव किया। तथापि, कंपनी ने यह दावा किया कि कंपनी केवल अलाभकारी कीमत की स्थिति में मालसूची बढ़ाने के लिए उत्पादन नहीं कर सकती। प्राधिकारी ने आगे यह जांच की कि क्या एच ओ सी एल का प्रचालन व्यवहार्य हो सकता है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनीलिन के पाटन से एच ओ सी एल को क्षति हुई है और कंपनी पाटन से उबरने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने यह दावा किया है कि जांच अवधि में भी कंपनी का योगदान सकारात्मक रहा है और 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर पर्याप्त सकारात्मक

योगदान होगा। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि हाइड्रोजन के कारण जी एन एफ सी की लागत में हाइड्रोजन की उत्पादन लागत का प्रदर्शन नहीं होता है। जी एन एफ सी द्वारा अपशिष्ट गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है और वह केवल हाइड्रोजन लागत हेतु अवसर लागत वसूलता है। जी एन एफ सी ने दावा किया कि यदि हाइड्रोजन में सही लागत प्रभावित की जाए तो उसकी लागत काफी अधिक होगी।

### पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

39. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ (ii) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है।"

### मांग एवं बाजार हिस्सा का निर्धारण

40. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की भारत में मांग अथवा स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और समस्त खोतों से हुए आयातों की राशि के रूप में किया है। इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में भी देखी जा सकती है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
मांग	मी.ट.	65,082	47,636	63,233	72,275
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	43,388	33,562	39,045	41,053
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	3000	5200	5200	5200
आयात-समस्त खोत	मी.ट.	18,694	8,874	18,987	26,022
<b>मांग में बाजार हिस्सा</b>					
घरेलू उद्योग	%	66.67%	70.46%	61.75%	56.80%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	4.61%	10.92%	8.22%	7.19%
संबद्ध देश	%	9.33%	0.00%	0.00%	5.33%
यूरोपीय संघ से आयात	%	2.80%	18.63%	29.99%	30.58%
अन्य देश	%	16.59%	0.00%	0.04%	0.09%

41 उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :

- i. यह देखा जाएगा कि जांच अवधि सहित क्षति अवधि में देश में उत्पाद की मांग में समग्र वृद्धि हुई है।
- ii. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा जो आधार वर्ष के बाद बंद हो गई थी, जांच अवधि में पुनः शुरू हो गई और अति उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- iii. घरेलू उद्योग की बिक्री में 2008-09 में गिरावट आई जिसमें 2009-10 तथा जांच अवधि में वृद्धि हुई लेकिन वह अभी भी आधार वर्ष से कम है।
- iv. इसके अलावा, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2008-09 में वृद्धि हुई, 2009-10 में गिरावट आई और जांच अवधि में आगे और गिरावट आई।

### आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

42 जांच अवधि के दौरान आयातों की वास्तविक मात्रा निम्नानुसार रही है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
अमरीका से आयात	मी.ट	5,978	-	-	3,852
जापान से आयात	मी.ट	96	-	-	-
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट	6074	-	-	3,852
यूरोपीय संघ से आयात	मी.ट	1,821	8,874	18,964	22,104
अन्य देशों से आयात	मी.ट	10,799	-	23	65
कुल आयात	मी.ट	18,694	8,874	18,987	26,022
<b>आयातों में बाजार हिस्सा</b>					
अमरीका	%	31.98%	0.00%	0.00%	14.80%
जापान	%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
संबद्ध देश	%	32.49	-	-	14.80
यूरोपीय संघ	%	9.74%	100.00%	99.88%	84.95%
अन्य देश	%	57.77%	0.00%	0.12%	0.25%
<b>मांग में बाजार हिस्सा</b>					
घरेलू उद्योग	%	66.67%	70.46%	61.75%	56.80%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	4.61%	10.92%	8.22%	7.19%
संबद्ध देश	%	9.33%	0.00%	0.00%	5.33%
यूरोपीय संघ से आयात	%	2.80%	18.63%	29.99%	30.58%
अन्य देश	%	16.59%	0.00%	0.04%	0.09%

43 उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और उसमें बढ़ोत्तरी हुई है ।
- ii. आयात मात्रा और अमरीका के परिणामी बाजार हिस्से में गिरावट आई है । यद्यपि यह काफी अधिक रहा है । यद्यपि, वर्ष 2008-09 और 2009-10 में अमरीका से शून्य आयात सूचित किए गए थे तथापि, जांच अधिक में आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है ।
- iii. आधार वर्ष में जापान से आयात मात्रा मामूली दर्ज की गई और बाद में वह बंद हो गई ।
- iv. इस बात पर विचार करते हुए कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि अमरीका से हुए आयातों का भारतीय मांग में काफी अधिक हिस्सा बना हुआ है ।

### कीमत प्रभाव

44. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपबंध है :-

"नियम 18 के उपनियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी समीक्षा जांच में इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या शुल्क समाप्त किए जाने के बाद कीमत प्रभाव की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । प्राधिकारी ने आगे यह निर्धारित किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में कम कीमत पर बिक्री होने की संभावना है ।

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :

विवरण	इकाई	मई 2010	जून, 2010	सितंबर 2010	ऑस्त
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
घ. उ. की बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***	***
अनुक्रमित	%	0-10	(0-10)	(0-10)	(0-10)

47.. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में अंतर काफी अधिक है जिससे यह पता चलता है कि पाटित सामग्री घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर रही है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जिन तीन महीनों में सामग्री का आयात हुआ है उनमें से एक माह में कीमत कटौती सकारात्मक रही है। लेकिन औसतन कीमत कटौती नकारात्मक है।

### कीमत हास और न्यूनीकरण

48. कीमत हास तब होता है जब क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत में घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना में आयात कीमत से कम रहती है। कीमत न्यूनीकरण वहाँ होता है जहाँ पाटन की वजह से कीमत वृद्धि में रुकावट आती है जिसमें अन्यथा कीमत में वृद्धि के कारण बढ़ोत्तरी हो जाती।

49. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	अक्टू.09- सितंबर.10
उत्पादन की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	112	107	102
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	106	99	109

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में 2008-09 में वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई। साथ ही साथ बिक्री कीमत में 2008-09 में वृद्धि हुई, 2009-10 में गिरावट आई और जांच अवधि में पुनः वृद्धि हुई। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्ष 2009-10 तक घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ और जांच अवधि में लाभ हुआ।

### घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के अन्य मापदंड

51. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति निर्धारण में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इसके अलावा नियमावली के अनुबंध-II (iv) में निम्नानुसार प्रावधान है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची,

रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

### उत्पादन, क्षमता तथा क्षमता उपयोग, बिक्री

52. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा के बारे में सूचना निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
क्षमता	मी.ट.	60,100	60,100	60,100	60,100
उत्पादन	मी.ट.	44,981	33,900	39,386	40,040
बिक्री	मी.ट.	43,388	33,562	39,045	41,053
क्षमता उपयोग	%	75%	56%	66%	67%
मांग	मी.ट.	65,082	47,636	63,233	72,275
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	66.67%	70.46%	61.75%	56.80%

53. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क्षति अवधि के दौरान मांग में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- उत्पादन में जांच अवधि में वृद्धि हुई। तथापि, यह आधार वर्ष की तुलना में कम स्तर पर रहा।
- बिक्री में भी उत्पादन के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।
- इसी समय मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई और परिणामतः घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा गंवाया।

### लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

54. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह की निम्नानुसार जांच की गई है :-

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	रु./ लाख	****	****	****	****
सूचीबद्ध		(100)	(204)	(286)	81
लगाई गई पूंजी पर आय	%	****	****	****	****
सूचीबद्ध		(100)	(220)	(460)	120

नकद लाभ	रु./मी.टन	****	****	****	****
सूचीबद्ध		(100)	(355)	(484)	215

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, जिसमें 2009-10 तक गिरावट आई, उसमें जांच अवधि में सुधार हुआ। यही प्रवृत्ति नकद लाभ तथा निवेश पर आय में भी देखी जाती है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लगाई गई पूँजी पर आय उचित स्तर से काफी कम रही है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि एचओ सी एल को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के अन्य कारक हैं। यद्यपि प्राधिकारी इस तर्क में कोई दम नहीं पाते हैं तथापि, प्राधिकारी ने जी एन एफ सी के निष्पादन की भी अलग से जांच की और यह नोट किया कि जी एन एफ सी का निष्पादन एचओ सी एल की तुलना में बेहतर है। तथापि, जी एन एफ सी की निवेश पर आय प्राधिकारी द्वारा विचारित उचित स्तर से कम है। साथ ही साथ यह नोट किया जाता है कि जी एन एफ सी द्वारा लागत आधार पर एनीलिन में हाइड्रोजन की लागत प्रभारित नहीं की जा रही है और इसे अवसर लागत आधार पर प्रभारित किया जा रहा है जो उत्पादन की सामान्य लागत से काफी कम है। यदि हाइड्रोजन की लागत को एनीलिन में प्रभारित किया जाता है तो कंपनी की लगाई गई पूँजी पर आय में वर्तमान स्तर की तुलना में अत्यधिक गिरावट आएगी। तथापि, प्राधिकारी ने तत्समय विद्यमान घरेलू उद्योग को हुई क्षति निर्धारित की है और लाभप्रदता का निर्धारण घरेलू उद्योग के प्रत्येक घटक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार की गई है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में यद्यपि सुधार हुआ है तथापि, वह कम रही है और घरेलू उद्योग अमरीका से सतत पाठन के कारण उचित लाभ कमाने में समर्थ नहीं रहा है। साथ ही साथ यूरोपीय संघ भी भारत में उत्पाद का पाठन कर रहा है जिसकी प्राधिकारी द्वारा अलग से जांच की जा रही है।

### रोजगार और मजदूरी

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के घटक बहु उत्पाद कंपनियां हैं और इसलिए घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर पर पाठन का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ सकता है। घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और मजदूरी की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
मजदूरी	रु./ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	113	145	142

57. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि में रोजगार के स्तर में मामूली गिरावट आई है। संदर्भ मजदूरी में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

### उत्पादकता में वास्तविक एवं संभावित गिरावट

58. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
प्रति दिन उत्पादकता प्रति	मी.ट./ दिन	***	***	***	***
कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./ संख्या	***	***	***	***

59. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में मामूली सुधार हुआ है। तथापि, उसमें आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

### मालसूची

60. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जिसे निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
औसत स्टॉक जो बिक्री दिवसों की संख्या के लिए पर्याप्त है	दिन	***	***	***	***

61. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर में भारी वृद्धि हुई और मांग में वृद्धि होने के बावजूद मालसूची जो आधार वर्ष में केवल 5 दिवस की बिक्री के लिए थी, अत्यधिक बढ़कर 20 दिन की बिक्री पर पहुंच गई।

### वृद्धि

62. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन तथा बिक्री में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा गंवाया, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ परंतु वे अभी भी विधिसम्मत स्तर से कम है और मालसूची में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि नकारात्मक रही। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, यूरोपीय संघ से हुए आयातों में वृद्धि के कारण पड़ा है न कि संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण क्योंकि वहां से हुए आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित कीमत से काफी अधिक है।

### पूंजी जुटाने की क्षमता

63. घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है। इस मामले में आगे और निवेश करने की उसकी क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तथापि, यदि वर्तमान स्रोत से पाटन जारी रहता है तो पूंजी जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

### पाटन की मात्रा

64. यह नोट किया जाता है कि अमरीका से पाटन मार्जिन सकारात्मक है। तथापि, जांच अवधि के दौरान जापान से संबद्ध वस्तु का कोई आयात न होने के मद्देनजर जापान हेतु पाटन मार्जिन की गणना नहीं की जा सकती।

### घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

65. घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव डालने वाले पाटित आयातों से इतर कारकों का विश्लेषण करने के लिए लागत संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, और घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से इस समीक्षा जांच की क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव डालने वाला कोई बाह्य कारक नहीं है।

### अन्य ज्ञात कारक:

### अन्य रूपों से आयात की मात्रा एवं कीमत

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से वर्तमान जांच में आयात हुए हैं और जिन अन्य देशों से आयात हुए हुए हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। संबद्ध देशों से इतर देशों से आयात की मात्रा काफी कम है और इसलिए उससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

### मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक वृद्धि हुई है। अतः मांग में कमी ऐसा संभावित कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

### विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रभाव एवं उनके बीच प्रतिस्पर्धा

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु मुख्य रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रबंधात्मक व्यवहार नहीं है। घरेलू उद्योग एक दूसरे के साथ और उसी

समय संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, अन्य रूपों से हुए आयात की मात्रा भारतीय बाजार में काफी अधिक है।

### प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात निष्पादन

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए हैं। इसके अलावा, संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया भी छिटपुट या तकनीकी या प्रौद्योगिकी विकास के साथ स्थिर रही है। याचिकाकर्ता और संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

### घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रचालनों के लिए अलग-अलग समस्त सूचना प्रस्तुत की है। अतः उपर्युक्त गंभीर क्षति केवल पाटन से ही हुई है।

### पाटन जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

71. पाटन जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. संभावना का निर्धारण एक भविष्यलक्षी निर्धारण है और प्राधिकारी को भविष्य के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए और ऐसे मुद्दों का समाधान करना चाहिए जिनकी वजह से शुल्क समाप्त किए जाने पर पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।
- ii. वर्तमान निष्पादन में सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ है और ऐसे मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच अपेक्षित होती है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई सतत क्षति नहीं हुई है तो घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना को लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में देखना अपेक्षित होता है।
- iii. संबद्ध देशों के निर्यातकों और उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी पाटित कीमत पर सामग्री का निर्यात जारी रखा। संबद्ध देशों आयातों का बाजार हिस्सा कम और ज्यादा था क्योंकि उन्हीं विदेशी उत्पादकों ने इ यू से उत्पाद की बिक्री की थी। घरेलू उद्योग की स्थिति में उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से के संबंध में गिरावट आई है। अतः घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उसे सतत क्षति हो रही है।
- iv. यदि जापान से कोई आयात न होने की स्थिति में जापान से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है तो यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या लागू पाटनरोधीशुल्क समाप्त किए जाने से पाटन की पुनरावृत्ति होगी। चूंकि संबद्ध देशों के उत्पादक और निर्यातक

भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का निर्यात करने में काफी आक्रामक हैं इसलिए क्षति की पुनरावृति होने की संभावना की जांच अति महत्वपूर्ण है।

v. वर्तमान पाटन का स्तर काफी अधिक है। इससे ही पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत सिद्ध होती है।

vi. अमरीका द्वारा तीसरे देशों को अत्यधिक पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है और यदि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो अमरीका निश्चित रूप से भारत 'में संबद्ध वस्तु के पाटन में इजाफा करेगा।

vii. भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतें विदेशी उत्पादकों के लिए काफी आकर्षक है। अमरीका द्वारा तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अमरीका पश्चात्याल्क लागू है और यूरोप पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और यह कि अमरीकी उत्पादक पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं कर रहे हैं।

viii. यदि वर्तमान मामले में वर्तमान शुल्क को समाप्त किया जाता है तो अमरीका न केवल संबद्ध वस्तु का पाटन बढ़ाएगा अपितु व यूरोप के समान कीमतें भी रखेगा।

ix. संबद्ध देशों के पास मांग की तुलना में अत्यधिक क्षमताएं हैं। अतः संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों के पास भारत में पाटित निर्यात बढ़ाने की क्षमता है।

x. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध निर्यातकों के पास पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताओं और भारतीय बाजार में उत्पाद की पर्याप्त मांग को ध्यान में रखते हुए यदि वर्तमान शुल्क को आगे जारी नहीं रखा जाता है तो आयातों में भारी वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग की बिक्री में आगे और गिरावट आएगी। संबद्ध उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क सम्मान किए जाने पर संबद्ध आयातों में भारी वृद्धि होगी।

xi. घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

xii. न्यायाधिकरण ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि पाटन द्वारा उस स्थिति में क्षति होगी यदि प्रचलित पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती सकारात्मक है; यदि किसी विशेष देश से कीमत कटौती नकारात्मक है, यदि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास या न्यूनीकरण होने की संभावना है और यदि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की न केवल बिक्री कीमत से अपितु घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से भी कम है।

#### निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

72. क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना के बारे में निर्यातकों, आयातकों और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार के विचार निम्नानुसार हैं:

- i. क्षति की संभावना और पुनरावृति का दावा मात्र अनुमानों पर आधारित है। भारतीय उद्योग की अतिरिक्त क्षमता और कीमत आकर्षकता किसी साक्ष्य से रहित है।

- ii. पिछले 10 वर्षों के दौरान जापान से आयात न के बराबर रहे हैं जिससे स्पष्टतः दीर्घावधिक स्वरूप में जापान से आयातों की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन का पता चलता है और इस प्रकार पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना से इंकार किया जाता है।
- iii. जापान से तीसरे देशों के निर्यात या तो शून्य हैं या नगण्य मात्रा में हैं। जापान एनीलिन का जरूरत के अनुसार आयातक है और देश में मांग की वजह से निर्यात में उत्तरोत्तर कमी की गई है।
- iv. याचिकाकर्ता का यह दावा वास्तविक साक्ष्य से समर्थित नहीं है कि अमरीका द्वारा अत्यधिक पाटित कीमत पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है।
- v. भारत में अमरीका से संबद्ध वस्तु की उत्तराई उस कीमत पर मानते हुए जिस पर उसने विश्व और चीन को निर्यात किया है तो कीमत कटौती नकारात्मक रहेगी। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की बराबरी करने के लिए अमरीका को काफी कम कीमत पर पेशकश करनी होगी जो उस स्थिति में संभव नहीं है जब वह तीसरे देशों को काफी अधिक कीमत पर सामग्री का निर्यात कर रहा है। अतः भारतीय बाजार अमरीका के लिए आकर्षक नहीं है।
- vi. अमरीका द्वारा निर्याति 77000 मी.ट. में से केवल 2000 मी.ट. (कुल निर्यातों के 3% से कम) का निर्यात भारत को किया गया है और वह भी निवल बिक्री प्राप्ति से काफी अधिक कीमत पर। 60,000 मी.ट. का निर्यात चीन को किया गया है जो अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बाजार है।
- vii. यह विवरण सत्यता से काफी दूर है कि अमरीका से होने वाले निर्यात ई यू को होने लगे हैं और उन्हें पुनः अमरीका को किया जाएगा। ये मात्र प्राधिकारी को भ्रम में डालने के लिए हैं।
- viii. यूरोप तथा अमरीका/जापान के उत्पादकों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। ऐसा एकमात्र उत्पादक है जिसका दोनों क्षेत्राधिकारों में संयंत्र है।
- ix. बेशी वैश्विक क्षमताओं का दावा करते हुए सूचना के स्रोत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे तालिका में दिए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता संदेहास्पद बन जाती है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

73. प्राधिकारी पाटन एवं क्षति की संभावना के बारे में प्रकटन विवरण के बाद किए गए अनुरोधों के संबंध में यह नोट करते हैं कि जहां तक अमरीका का संबंध है, विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त आयात हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अमरीका में 1,90,000 मी.ट. की मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है जो समूची भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्राधिकारी ने अमरीका में बेशी क्षमता के बारे में मर्चेन्ट रिसर्च एंड कंसल्टिंग लिमिटेड की रिपोर्ट पर विचार किया है। अमरीका में वर्ष 2010 में बेशी क्षमता का निर्धारण अमरीका में मांग के अनुसार घटी हुई कुल क्षमता और भारत सहित सभी देशों को अमरीका द्वारा किए गए निर्यातों को ध्यान में रखकर किया गया है। बेशी क्षमता की गणना उक्त रिपोर्ट के अनुसार 97037 मी.ट. के रूप में की गई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह

सिद्ध नहीं किया है कि जब उनकी कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित कीमत से पहले ही अधिक है तो वे भारतीय बाजार में कम कीमत पर किस प्रकार प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, अमरीका द्वारा भारतीय बाजार से इतर विदेशी बाजारों में भी उच्च कीमत वसूली जा रही है। व्यापार का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है न कि धाटे को उठाना अथवा उसमें वृद्धि करना। बेशी क्षमता की मात्र उपलब्धता स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि किसी संबद्ध देश, वर्तमान मामले में अमरीका से पाटन शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पुनः होगा अथवा वह जारी रहेगा और उससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध में कोई तर्क नहीं है कि जब यूरोपी संघ द्वारा घरेलू उद्योग की कीमत पर भारी कटौती की जा रही है तो संबद्ध देशों द्वारा उसकी कीमत पर निर्यात किया जाएगा जिससे घरेलू उद्योग के लिए अत्यधिक कीमत कटौती होगी और घरेलू उद्योग कीमत घटाने के लिए बाध्य होगा।

74. इसके अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, यूरोपीय संघ से हुए आयातों के कारण हुई है क्योंकि जांच अवधि में यूरोपीय संघ से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई हुई है और न ही संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति होने की संभावना है।

### क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

75. क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना समान विवरण वाले संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। यह विश्लेषण माह दर माह आधार पर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और यह मानने के बारे में प्राधिकारी की संगत परंपरा रही है कि क्षति रहित कीमत-निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

एन आई पी (रु. प्रति किग्रा.)	***
पहुंच कीमत (रु. प्रति किग्रा.)	***
क्षति मार्जिन (रु. प्रति किग्रा.)	***
पहुंच कीमत के % के रूप में क्षति मार्जिन	5-15%

प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग और व्यापारी, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध।

76. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग और व्यापारी, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के उचित शीर्षों में वर्तमान जांच के लिए संगत पाई गई सीमा तक इन पर विचार किया है। आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

क. यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि एच ओ सी एल को दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि एच ओ सी एल को क्षति अन्य कारकों की वजह से हुई है। एच ओ सी एल को हुई क्षति से समग्र क्षति विश्लेषण गड़बड़ा गया है।

ख. एच ओ सी एल द्वारा दिए गए आर टी आई उत्तर में यह दर्शाया गया है कि स्टॉफ का कोई संचयन नहीं हुआ है।

ग. पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। आयातकों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा क्षति रहित कीमत से अधिक है। अमरीकी उत्पादकों के पास चीन में बेहतर बाजार है इसलिए इस बात की संभावना नहीं है कि वे भारत में उत्पाद का पाटन करेंगे।

घ. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों में और विश्व में वर्ष 2006 के आंकड़ों के आधार पर मांग में वृद्धि से संबंधित तथ्यों की अनदेखी करते हुए बेशी क्षमता का दावा किया है।

इ. याचिकाकर्ता वैश्विक बेशी स्थिति की झूठी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है और यह कह कर प्राधिकारी को गुमराह कर रहा है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में ऐसी बेशी क्षमता भारतीय बाजार में आ जाएगी। जब संबद्ध देशों से पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई खास आयात नहीं हुआ था तो पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार को भर देने के लिए इस क्षमता को सुरक्षित रखने की इन देशों में गुजाइश नहीं है और यह मात्र कल्पना है।

घ. पाटनरोधी जांचें देश विशिष्ट होती हैं अतः घरेलू उद्योग का यह तर्क विधिक आधार से रहित है कि अमरीकी उत्पादक यूरोपीय संघ के कीमत स्तरों पर भारत को निर्यात करेंगे।

ज. मात्रा के संबंध में जांचोत्तर अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

झ. कीमत कटौती नकारात्मक है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक है और कीमत में कोई हास तथा न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

ट. प्रकटन विवरण में आयात के गलत आंकड़ों पर विचार किया गया है।

ठ. भाग न लेना पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग के लाभ उचित स्तर से अधिक हैं।

ढ. भारतीय आयातकों ने पाटन मार्जिन की गणना प्रदान की है जिससे यह पता चलता है कि निर्धारित पाटन मार्जिन नकारात्मक है।

ण. एच ओ सी एल की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि वर्ष 2006-07 में रासायनी संयंत्र को तकनीकी और रखरखाव के लिए बंद किया गया था।

त. एच ओ सी एल को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों के कारण कोई उचित कारणेतर विश्लेषण, क्षति जांच नहीं की गई है।

थ. पैरा-19 में हाइड्रोजन की लागत से संबंधित विवरण एक सामान्य विवरण है जिसमें प्राधिकारी द्वारा किए गए दावे के समर्थन तथा मिलान हेतु कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है और इसलिए नोसिल को इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने हेतु पर्याप्त सूचना से वंचित किया गया है।

द. एच ओ सी एल की तकनीकी बाधा की जांच हेतु 13 वर्ष पुराने उत्पादन पर भरोसा किया गया है। यह पूर्णतः अवैध, अभूतपूर्व और कानूनन प्राधिकृत नहीं है।

ध. जांच के इस चरण पर एच ओ सी एल को घरेलू उद्योग में शामिल करना पूर्व उदाहरणों के असंगत और विधिसम्मत नहीं है। घरेलू उद्योग के घटकों में मर्जी के अनुसार और याचिकाकर्ता की सुविधा के अनुसार परिवर्तन करना उचित नहीं हो सकता है।

न. पाटन मार्जिन की गणना को गोपनीय रखने की कोई जरूरत या औचित्य नहीं है। सामान्य मूल्य तथा कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई सूचना व्यापार स्वामित्व वाली सूचना नहीं है। इसके बजाए यह सार्वजनिक क्षेत्र से ली गई सूचना है जिसका प्रकटन किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार गोपनीयता की आड़ में निर्यात कीमत को छिपाने में कोई औचित्य नहीं है।

प. उत्पादन लागत के बारे में एच ओ सी एल की अकुशलता को 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग लेकर क्षति रहित कीमत में वृद्धि करने के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। बहरहाल एच ओ सी एल की अकुशलता पाटन एवं क्षति को ध्यान में रखते हुए अब से कई वर्ष पूर्व से विद्यमान है। इसके अलावा, अनुबंध-III हाल के संशोधन के बाद अब क्षति रहित कीमत की गणना के बारे में स्पष्ट है। क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान सर्वोत्तम उपयोग दर पर सभी कारक लिए जाते हैं। क्षति अवधि या जांच अवधि में किसी भी समय एच ओ सी एल का क्षमता उपयोग 100% के आस-पास नहीं रहा है।

77 घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं :-

- क. चूंकि परिकलित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की सूचना पर आधारित है इसलिए यह घरेलू उद्योग की ओर से गोपनीय नहीं हो सकता है।
- ख. कार्यशील पूँजी के परिकलन में गणना संबंधी त्रुटि हुई है। इसके अलावा कतिपय ऋणधारकों की अनुमति नहं दी गई है जो गतत है, इसके अलावा, यद्यपि, अशोध्य ऋणों को लागत का हिस्सा नहीं माना गया है तथापि, कार्यशील पूँजी से अशोध्य ऋणों के प्रावधान को हटाया नहीं गया है।
- ग. न्यूनतम क्षति रहित कीमत के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली से असंगत है और घरेलू उद्योग के हित के विरुद्ध है। निर्धारण के समय घरेलू उद्योग की असाधारण लागत को उसी समय हटाया गया है, असाधारण लाभ को नहीं हटाया गया है जिससे निर्यातकों को उनके असहयोग के लिए अनावश्यक लाभ पहुंचा है।
- घ. घरेलू उद्योग में भारत, चीन, ई यू आदि सहित वैश्विक देशों को अमरीका से निर्यातों के आंकड़े संग्रहीत किए हैं। यह देखा जा सकता है कि चीन को निर्यातों में 2010 तक वृद्धि हुई है और 2011 में अक्टूबर की अवधि ~~लार्क~~ भारी गिरावट आई है। यही आंकड़े दर्शाते हैं कि ई यू को हुए निर्यातों में भी वृद्धि हुई है और भारत को हुए निर्यात अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में कम कीमतों पर किए गए हैं।
- ड. क्षति अवधि के लिए एच ओ सी एल की डाउन टाइम रिपोर्ट दर्शाती है कि कंपनी के एनीलिन संयंत्र के उत्पादन को कम ऑफटेक, अनार्थिक बाजार दशाओं और अन्य कारकों के कारण रोक दिया गया था। इसका विश्लेषण यह दर्शाता है कि यदि अन्य कारकों के प्रभाव को हटाया भी जाए तो भी एच ओ सी एल के उत्पादन में भारी गिरावट आई है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

78. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा, उठाए गए मुद्दों की निम्नानुसार जांच की है :-

- क. एच ओ सी एल को बाहर रखने से संबंधित मुद्दे पर पहले ही उपर्युक्त ढंग से विचार किया गया है और प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों से कोई नया अनुरोध नहीं मिला है और वह दोहराई गई प्रकृति के हैं।
- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एच ओ सी एल द्वारा दिया गया आर टी आई का उत्तर केवल एक एनीलिन संयंत्र के संबंध में था जबकि कंपनी के पास 3 एनीलिन संयंत्र हैं।

इस प्रकार एक संयंत्र के लिए आर टी आई का उत्तर कोई सार्थ दिशा-निर्देश प्रदान नहीं कर सकता है ।

ग. आयात आंकड़ों के प्रयोग के संबंध में यह बताया गया है कि ये डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त नहीं किए गए हैं और उनका सही ढंग से प्रयोग हुआ है । इसके अलावा, पाटन मार्जिन के निर्धारण में कोई विसंगति नहीं है ।

घ. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के प्रकटन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में कोई तथ्य नहीं मिला है क्योंकि यह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदत्त गोपनीय सूचना पर आधारित हैं जिसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

ड. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एच ओ सी एल की क्षति रहित कीमत निर्धारित की है । इसके अलावा, एच ओ सी एल की क्षति रहित कीमत 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर निर्धारित की गई है ताकि अन्य कारकों से हुई कुल क्षति समाप्त की जा सके ।

च. क्षति रहित कीमत की गणना में त्रुटि के संबंध में प्राधिकारी ने परिकलन की समीक्षा की है और जहां आवश्यक पाया गया परिकलन की त्रुटियों में सुधार किया गया है । कुछ वर्तमान परिसंपत्तियों की अनुमति नहीं देने के संबंध में प्राधिकारी ने संगत प्रक्रिया का पालन किया है जिसके आधार पर कठिप्पय परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है ।

छ. जहां तक एच ओ सी एल की डाउन टाइम रिपोर्ट का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा उसका विश्लेषण किया गया है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह किसी क्षति विश्लेषण में बदलती नहीं है । विरोधी पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा डाउन टाइम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना स्पष्टतः दर्शाता है कि अन्य कारकों के अलावा कम ऑफटेक और अनार्थिक बाजार दशाओं के कारण एच ओ सी एल का संयंत्र बंद पड़ा है । प्राधिकारी ने इसका विस्तृत विश्लेषण किया और यह नोट किया कि अन्य कारकों के प्रभाव को शामिल नहीं करने के बाद भी घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट की प्रवति प्रदर्शित हुई है ।

### पाटन और क्षति की संभावना

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में अमरीका के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है तथापि, जांच अवधि में अमरीका का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित कीमत से अधिक रहा है । प्राधिकारी ने अमरीका से तीसरे देशों को निर्यातों के पहुंच मूल्य की भी गणना की है और यह पाया कि यह भारतीय बाजार के लिए पहुंच मूल्य की तुलना में भी अधिक है । इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों से निर्यातों को भारतीय बाजार में

प्रवेश नहीं मिलेगा । इसके अलावा, अमरीका से आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित कीमत से काफी अधिक कीमत पर किए गए हैं ।

80. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इन दावों की भी जांच करते हैं कि अमरीका में 1,90,000 मी.ट. की मुक्त रूप से निपटान योग्य उपलब्ध क्षमता है, जो समूची भारतीय मांग पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त है । जैसा ऊपर बताया गया है, प्राधिकारी ने अमरीका में बेशी क्षमता से संबंधित मर्चेन्ट रिसर्च एंड कन्सल्टिंग लिमिटेड की रिपोर्ट पर विचार किया है । 2010 में अमरीका में बेशी क्षमता को अमरीका में मांग को कुल मांग से घटा कर और भारत समेत सभी देशों को अमरीका द्वारा निर्यातों पर विचार करते हुए किया गया है । उक्त रिपोर्ट के अनुसार बेशी क्षमता 97037 मी.ट. की है । तथापि, घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध नहीं किया है कि ये कैसे कम कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर लेगी जबकि उन्हें घरेलू उद्योग की एन एस आर और एन आई पी से उच्चतर कीमत पहले ही प्राप्त हो रही है । इसके अलावा, जैसा ऊपर बताया गया है, अमरीका को अन्य बाजारों में भारतीय बाजार से अधिक कीमतें प्राप्त हो रही हैं । व्यापार का उद्देश्य लाभों को अर्जित करना और उन्हें अधिकतम बनाना है न कि धाटे को उठाना या उसे बढ़ाना है । केवल बेशी क्षमता की उपलब्धता का तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यदि शुल्क को हटाया जाता है तो संबद्ध देश वर्तमान मामले में अमरीका से पाटन की पुनरावृत्ति होगी अथवा वह जारी रहेगा । इसके अलावा, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का कोई औचित्य नहीं है कि जब यूरोपीय संघ घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहा है तो अमरीका भी कीमतों के उसी स्तर पर निर्यात करेगा जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें घटाने पर बाध्य होना पड़ेगा ।

81. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस तर्क की भी जांच की है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो यूरोपीय संघ से निर्यात अमेरिका के रास्ते भारत में आ सकते हैं । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच की है और यह पाया है कि ये केवल आशंकाएं हैं । यह तथ्य कि कुछ उत्पादकों के संयंत्र ई यू और अमरीका में हैं, उनके इस तर्क को सिद्ध नहीं करो है कि ई यू से होने वाले आयात अमरीका के रास्ते आएंगे क्योंकि अमरीका के मामले में माल भाड़े का भार अधिक होगा और अमरीका से संबद्ध वस्तु की कीमतें किसी भी परिस्थिति में अधिक रहेंगी । घरेलू उद्योग अपने दावे के समर्थन में रिकॉर्ड में तथ्यपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराने में भी विफल रहा है । अतः घरेलू उद्योग से किसी वास्तविक साक्ष्य के अभाव में और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के अनुरोधों में कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है ।

82. उपर्युक्त के भद्रेनजर यह निष्कर्ष है कि अमरीका से आयात किसी भी तरह से ऐसी कीमतों पर नहीं होंगे जिससे शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ।

83. जैसा ऊपर नोट किया गया है, जापान के संबंध में 2007-08 में नगण्य आयातों को छोड़कर क्षति जांच अधिक के दौरान जापान से कोई आयात नहीं हुआ है । इसके अलावा, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध सूचना के अनुसार जापान की क्षमता 3,98,000 मी.ट. है और वास्तविक उत्पादन 2,79,000 मी.ट. है । तथापि, जापान में बेशी क्षमता के बावजूद उनके द्वारा भारत को तथा अन्य देशों को कोई निर्यात नहीं हुए हैं । इससे पता चलता है कि उनके लिए भारतीय बाजार महत्वपूर्ण नहीं है और शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में आयातों के मार्ग बदलने की कोई वास्तविक संभावना प्रदर्शित नहीं होती है । ऐसी स्थिति में प्राधिकारी

पाते हैं कि जापान से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुनरावृति की कोई संभावना नहीं है।

### भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

84. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से भारत में विचाराधीन उत्पाद की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय के अधिरोपण से पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का हास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प बनाए रखने में सहायता मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय के अधिरोपण से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर रोक नहीं लगेगी और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

85. प्राधिकारी यह मानते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के समान्य हित में है।

### निष्कर्ष

86. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना तथा किए गए अनुरोधों एवं इन अंतिम जांच परिणामों में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं परिणामी क्षति जारी रहने की स्थिति तथा पाटन एवं क्षति जारी रहने/उसकी पुनरावृति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

- (क) अमरीका द्वारा भारत को एनीलिन का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
- (ख) आधार वर्ष 2007–08 में थोड़े से आयातों को छोड़कर क्षति जांच अवधि में जापान से कोई आयात नहीं हुए हैं।
- (ग) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
- (घ) यदि संबद्ध देशों से एनीलिन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की कोई संभावना नहीं है।

### सिफारिशें

87. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृति होने की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी संबद्ध देशों पर लागू शुल्कों को हटाने की सिफारिश करते हैं।

38. केन्द्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

#### Final Findings

**Subject :** Sunset Review investigation concerning import of Aniline originating in or exported from the USA and Japan.

**No. 15/19/2010-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, (hereinafter referred as the Rules or the AD Rules) thereof:

#### BACKGROUND

1. Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as "the Rules"), the Designated Authority (hereinafter referred to as "the Authority") initiated a Sunset Review antidumping investigation vide Notification No. 15/19/2010-DGAD dated on 20<sup>th</sup> December, 2010 into alleged dumping of Aniline originating in or exported from the USA and Japan (hereinafter referred to as "the subject countries"). Definitive antidumping duty in the original investigation was recommended by the Authority on the imports of Aniline from the USA and Japan vide Notification No. 33/1/99-DGAD dated 31.8.2000, and definitive antidumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 128/2000-Customs dated 6th October, 2000.
  
2. And whereas, the Authority considered that the sunset review of the anti-dumping duty recommended would be appropriate to review as to whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury under the provision of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended, and after conducting the review, the Authority issued the Final Findings vide Notification No.

15/2/2005-DGAD dated 5th April, 2006. The Department of Revenue imposed definitive antidumping duty on the subject goods from the subject countries vide Notification No. 58/2006-CUS dated 9th June, 2006.

3. And whereas, the Rules require the Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of anti-dumping duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it, that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.
  
4. In terms of the above provision, Designated Authority, received an application filed by the Domestic Industry substantiating the need for second sunset review of the anti dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from the USA and Japan and requesting for enhancement / revision of the anti dumping duty imposed on the subject goods.

### PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
  - i. The Designated Authority, in line with the order passed by the Hon'ble High Court of Delhi in WP No. 16893 of 2006, initiated Sun-Set Review in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti Dumping Rules to examine whether cessation of duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority issued a public notice dated 20th December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, and initiated antidumping sunset review investigation concerning the imports of Aniline originating in or exported from the USA and Japan.
  - ii. The Authority received an application filed by M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited requesting the initiation of the investigation for continuation of antidumping duties in force concerning the imports of Aniline originating in or exported from the USA and Japan.
  - iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known producers and/or exporters in the subject countries and provided them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2).

S.N.	Name of Company	Country
1.	M/s. Sumitomo Chemical Company Limited	Japan

2.	M/s. Mitsui & Co. Ltd.	Japan
3.	M/s. Bayer Corporation	USA
4.	M/s. BASF Corporation	USA
5.	M/s. DUPONT	USA

- iv. None of these exporters/producers from the subject countries filed any response to questionnaire in the form and manner prescribed.
- v. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 5(5), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- vii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers, consumers, industrial users of the subject goods in India and advised them to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

S.N.	Name of Company	S.N.	Name of Company
1.	Aarti Industries Ltd., Mumbai	2.	Abir Chemicals Ltd., Ahmedabad
3.	Alginates Allied Chemicals P Ltd, Badlapur	4.	Alpha Dyes & Chemicals, Ahmedabad
5.	Anirox Pigments Ltd., Kolkata	6.	Asiatic Color Chem Industries, Ahmedabad
7.	Atul Ltd., Hyderabad	8.	Bayer India Ltd., Mumbai
9.	Beck (India) Ltd., Pune	10.	Bhageria Dyechem Ltd., Mumbai
11.	Diamond Dyechem, Mumbai	12.	Ganesh Chemicals Industries, Mumbai
13.	Hindustan Inks & Resins Ltd., Vapi	14.	Industrial Solvents & Chemicals Ltd., Mumbai
15.	International Dyestuff Industries, Vadodara	16.	Jay Chemical Industries Ltd., Ahmedabad
17.	Mangalam Drugs & Organics Mumbai	18.	Meghmani Dyes & Intermediates, Ahmedabad
19.	Metrochem Industries Ltd., Ahmedabad	20.	M/s National Organic Chemical Industries Ltd., Mumbai
21.	Nutan Dyechem, Surat	22.	Pandasara Industries Ltd., Pandasara
23.	Ravi Dyeware Co. Ltd., Mumbai	24.	Roop Dyes & Intermediates, Surendranagar
25.	Sonkamal Enterprises P Ltd., Mumbai	26.	Vipul Dyechem Ltd., Mumbai
27.	Schenectady Beck (India) Ltd., Mumbai		

viii. The following importers/users/user associations filed the response to the questionnaire in the form and manner prescribed.

S.N.	Name of Company
1.	M/s NOCIL Ltd.
2.	Ravi Dyeware Co. Ltd.
3.	Kutch Chemicals Industries Ltd.
4.	Industrial Solvents & Chemicals Pvt. Ltd.
5.	M/s Dye Stuffing Manufacturing Association of India

ix. Request was made to the Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata, to provide details of imports of the subject goods in India for the period of investigation and preceding three years. Information was received from the DGCI&S.

x. The Authority provided the copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, whenever requested.

xii. Investigation was carried out for the period of investigation (POI) starting from October, 2009 to September, 2010. However, injury examination was conducted for a period from 2007-08, 2008-09, 2009-10 and the POI.

xiii. The Authority held an oral hearing on 4<sup>th</sup> August, 2011 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6(6). The parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments/rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Designated Authority has considered submissions received from various interested parties appropriately.

xiv. Arguments raised and information/evidence provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

xv. The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the adequacy and accuracy of the information supplied. For that purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary.

xvi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties through a public file maintained

by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xvii. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis under consideration of the Authority are being disclosed to the known interested parties and comments received on the same shall be considered in the final findings.

xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.

xix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xx. \*\*\* in the Final Findings represents the information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.

### PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

#### Views of the Domestic Industry

6. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:

- The present review investigation is a sunset review investigation. The product involved in the original investigation, the first sunset review investigation and in the present sunset review investigation is Aniline. The product under consideration in the present sunset review is the same as has been held by the Designated Authority in the original investigation.
- Aniline is a transparent, oily liquid and a primary amine compound. Its color transforms to light pale yellow liquid when freshly distilled. Its color darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. Aniline is also used in some other industries such as rubber chemicals, explosives, resins etc.
- The subject good is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading no. 2921.41. However, customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the

present investigation. This information has been correlated with the information provided by responding foreign producers.

- iv. There is no difference in the product produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. Aniline produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology (followed by most of the producers' world over), functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Aniline produced by the petitioners and imported from the subject countries are like article.
- v. Present investigation is a review investigation. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigations, which is relied upon.

#### Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

7. None of the importers, consumers, producers/exporters and any other interested party has filed any comments or submissions with regard to the product under consideration, and like articles.

#### Examination by The Authority

8. Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules specifies that like article means an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under examination.
9. Product under consideration is Aniline, which is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound which finds application in such industries as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. Aniline is also used in some other industries such as rubber chemicals, explosives, resins etc. Aniline is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading no. 2921.41. However, customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
10. The petitioner claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. The Authority notes that Aniline produced by the domestic industry has characteristics, which are similar to those of Aniline imported from the subject countries. In view of the above, the Authority holds that Aniline produced by the domestic industry and that being imported from the subject countries are like articles within the meaning of the Rules. The Authority also holds that Aniline is

classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading no. 2921.41 and that the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

## **DOMESTIC INDUSTRY**

### **Views of the Domestic Industry**

11. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to initiation and standing of the domestic industry:
  - i. The present investigation has been undertaken by the Designated Authority on the request filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited (GNFC). The other major producer, Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), has also submitted the relevant information to the Designated Authority. The non-confidential version of the same was also made available for the interested parties.
  - ii. The petition has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizer Co Limited. Subsequent to the initiation of the investigation, the Authority has sent communication to all interested parties including HOCL, and HOCL accordingly, filed the costing and injury information. Therefore, it is incorrect to state that it is an effort to change the constituents of the domestic industry. HOCL was part of the domestic industry in the earlier investigations also.
  - iii. The Designated Authority is required to consider "domestic industry as a whole" for assessment of injury.
  - iv. It is only when information with regard to domestic producers as a whole is not available and when domestic producers as a whole are not before the Designated Authority that the Designated Authority is permitted under the law to consider those domestic producers whose collective output constitute a major proportion in eligible Indian production. Thus, in a situation where information has been made available by HOCL, its data cannot be rejected.
  - v. None of the companies has preferred non-cooperation or is withholding any information required by the Authority. Under the circumstances, the Authority should determine the scope of domestic industry as GNFC and HOCL.
  - vi. With respect to insufficient data in the petition and consideration of different period of investigation by the Authority, petitioner submits that the petition was filed with data for certain period whereas the Designated Authority initiated the investigation with a different period, over which the domestic industry had no control. There is no legal basis shown establishing that the data in the petition and the period considered by the Authority should be the same. Neither does it imply that the investigating authorities should have a petition for that period before initiating the investigations.
  - vii. Period in the petition and the period of investigation taken by the Authority for detailed investigations are two different parameters and are being mixed by the interested parties without any legal and factual basis. None of the

contesting parties justified the prejudice caused to them by the initiation of the present investigation. As far as updated petition is concerned, the same is not required to be filed as the petition is required to be filed for initiation of the investigation prior to initiation.

viii. The quality of information and evidences at the level of initiation and final determination are absolutely different as has been held by the WTO in the matter concerning Guatemala. Domestic industry submits that quality of evidence increases as the investigation progresses. Domestic industry cannot be expected to provide any information more than what is reasonably available.

ix. NOCIL has not filed any questionnaire response and the submissions of others do not provide any proper and meaningful non confidential summary of the information contained in the response.

x. The interested parties themselves have not followed the prescribed requirements under the AD Rules. NOCIL has not filed importer questionnaire response. Dye Stuff Manufacturer's Association has not furnished any information establishing the interest and the impact on its members. Further, no detail has been made available about its members and other quantitative details concerning the imports made by its members, purchases, prices etc.

#### Views of the Exporter/producer, Importers, Consumers And Other Interested Parties

12. None of the exporters has responded in the present investigation. However, the importers, consumers, and other interested parties have filed the following comments with regard to the standing of the domestic industry:

- i. There is a difference in the POI and injury period in the petition and the initiation notification. Designated Authority did not provide the data based on which it changed the period of investigation.
- ii. The application in the public file was for a different POI (April 2009 to June 2010) and injury analysis was taken from 2006-07 whereas the POI as per initiation notification is Oct. 09 to Sept. 2010 and injury analysis is taken from 2007-08 onwards.
- iii. Designated Authority being a quasi-judicial Authority, any decision taken on changing the period of investigation from that of the petition has to be reasonably exercised especially when a parallel investigation is being undertaken initiated on the same day as that of the current case.
- iv. Non-confidential version of the application was filed on 30th December, 2010. However, even on the repeated request, the copy of the application was provided to the importer on 19th May, 2011. The information with respect to the POI fixed by the Authority was not made available in the application. The updated information was received by the importer on 27th July only.
- v. In fact, filing the non-confidential version of the application subsequent to the initiation is not permitted under the law. This shows that the applicant has not filed completed and updated petition in the form and manner mandated by the AD Rules.

- vi. The non-confidential version of the petition is wholly deficient and has seriously hampered our right to comment upon the same.
- vii. Petition was filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizer Company Ltd alone. Subsequently, it gave consolidated injury information for the domestic industry as a whole without naming the participating companies. No authorization is there in the public file. Thus, HOCL as petitioner is done without fulfilling the requirement of law, and therefore, HOCL data should not be considered by the Authority.
- viii. In the hearing it was clarified on behalf of the DA that HOCL has not filed any authorisation letter in the name of any consultant for data submission or to attend the public hearing. The reply by the consultant that it is a minor issue is unheard of, as if it is open for the participants to decide the magnitude of any such matter which requires strict compliance. This was all deliberately web netted by the consultant to evade an ADD Rule in relation to whether a company data can be considered as a part of domestic industry.
- ix. It is unjustifiable attempt to change the constituents of the domestic industry after the initiation. The same has been prohibited in the caustic Soda from Thailand, Chinese Taipei and Norway and mid-term review of Caustic Soda from Saudi Arabia, Korea RP and USA. The same has been held in Mexico-anti-dumping duties on steel pipes and tubes from Guatemala.
- x. The continuous recasting and re-constitution of the domestic industry subsequent to the initiation is not permitted.
- xi. The petitioner's argument in the public hearing that domestic industry should be taken as a whole so as to include the remaining domestic producers is misplaced, as the court held that the NIP must be calculated for the domestic industry as a whole for the PUC. Further, EC Bed Linen referred by the domestic industry, has held that the investigating Authorities cannot consider only a sample of domestic industry while assessing injury. The DA deviated from this practice in the matter of caustic soda.
- xii. Since, HOCL was shut down for a period of 5-6 months, the data for the same should not be considered.
- xiii. The petitioner has not updated the reasoning on injury, threat of injury and dumping in the revised petition.

### Examination By the Authority

13. The Authority notes that the petition has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited. Subsequent to the initiation of the investigation, communication was sent to all interested parties including other producers of product concern in India. HOCL responded to the initiation of the investigation as a producer and provided costing and injury information, which has been verified by the Authority.
14. The Authority notes that it is claimed by interested parties that HOCL was shut down for 5-6 months and there are other factors of injury to HOCL and, therefore, HOCL should be excluded from the purview of the domestic industry. The Authority notes that HOCL was not actually shut down but it had only suspended its production due to significant inventories. There is no

technical constraint or reason for suspension of production by HOCL. At the time of suspension of production, the company had sufficient inventory to meet the sales at that point of time. The Authority concludes that the interested parties failed to put cogent reason as to why the company should be excluded from the scope of the domestic industry.

15. The Authority further notes that Rules provide exclusion of a producer from the scope of domestic industry only in case of imports or relationship with importers/exporters. The Authority holds that GNFC and HOCL account for a major proportion of the total Indian production and constitute domestic industry as a whole within the meaning of the Rules.

16. The investigation period considered in the petition and in the notice of initiation is different, which has been disputed by the interested parties. The Authority notes that there is no legal requirement that the investigation period in the petition filed before the Designated Authority and the investigation period chosen by the Designated Authority for detailed investigations should be the same. The Authority considered a period for the purpose of detailed investigation. Accordingly, the domestic industry filed revised data after initiation of investigation, which has been made available to interested parties through public file.

17. It has also been argued that there is another investigation initiated by the Authority wherein the investigation period is different. The Authority notes that there is no legal requirement that the investigation period in different investigations should be the same.

18. It is clarified by the Authority that the data made available for the investigation period by the petitioner was made available to the interested parties through public file and they have been given sufficient opportunity to comment on the same.

19. As regards filing of information by HOCL or authorization for filing the information of HOCL, the Authority notes that the information was filed by HOCL through its counsel, who was duly authorized. Further, the Authority holds that HOCL data should be included within the scope of domestic industry for the purpose of injury analysis. The mere fact that HOCL's performance might have been impacted due to other factors does not imply that the company should be excluded from the scope of domestic industry. In fact, a situation where the performance of the domestic industry has been impacted by other factors is clearly addressed under the law itself, which requires the Authority to segregate injury caused to the domestic industry by such other factors. Thus, if HOCL has suffered injury because of other factors as well, it would be inappropriate to exclude the company on this account. Instead, the Authority is required to adjust HOCL's performance for such other factors. The investigation has shown, as opposed to claim made by interested parties, that HOCL does not have any technical constraint in operating the plant. In fact, HOCL had achieved a production of 24128 MT in the year 1997-98. The Authority further notes that a comparison of hydrogen or aniline cost of production of HOCL with GNFC would not be appropriate for the reason that GNFC does not have stand alone hydrogen production. Cost of GNFC on account of hydrogen is not reflective of the cost of production of hydrogen. GNFC produces hydrogen from waste gas and charges only opportunity cost to hydrogen cost. The cost of production on stand-alone basis claimed by GNFC based on quantified and verified data shows that its actual cost of

production of hydrogen would have been much higher than the amount charged at present. The domestic industry in fact argued that GNFC's cost of production should be appropriately revised upward by considering reasonable cost of production of hydrogen instead of the actual expenses reported by the company on this account. The Authority also notes that the Rules require assessment of injury to the domestic industry and, therefore, individual assessment of constituents of the domestic industry would not be appropriate. The Authority, however, notes that the trends in performance, particularly with regard to price parameters; for both GNFC and HOCL, are the same, i.e., their profitability and consequently cash profits and return on investment deteriorated significantly over the period.

20. It has been argued that the constituents of the domestic industry should not be changed after initiation of investigations. The Authority holds that there is no legal basis for such a claim. On the contrary, the Authority is required to determine scope of the domestic industry at each stage of the proceedings. In fact, one of the purposes of initiation of investigation is to call relevant information from all relevant parties; and if one or more other domestic producers files information before the Authority after initiation of investigations, the Authority is required to include such information for the purpose of assessment of injury. As regards reference to caustic soda case made in this regard, the Authority notes that it has not been established that the facts of the two cases are the same and exclusion of HOCL is justified on this account. On the contrary, there are cases where information for more producers was added during the course of the investigations. The Authority further notes that anti-dumping investigation is a process where quality and quantity of evidence improves as the investigation progresses. Mere closure of HOCL for some period due to significant inventories does not imply that its data should be excluded for the purpose of assessing injury.

## CONFIDENTIALITY

### Views of the Domestic Industry

21. Following submissions have been made by the domestic industry:

- Reasons claiming various adjustments made from the export price, has not been kept confidential, it is clearly stated in the petition that the adjustments on these accounts are based on market information of petitioner and the conservative estimates.
- Domestic Industry submits that the costing information is by nature confidential and the confidentiality for such information is allowed even by the Authority. Prescribed format also permits confidentiality on this account.
- Selling price given in the annual report of the Company is not net sales realization. There are various adjustments and discounts in gross price.

### View of Exporters/Importers and Other Interested Parties

22. Following submissions have been made by the exporters/importers and other interested parties:

- i. The applicability of Rules and law with respect to the Confidentiality should be made applicable to the petitioner as well. Petitioner has claimed confidentiality regarding the information ought to have been disclosed like, source of freight and other overhead expenses.
- ii. It seems that the petitioner has applied inflated rates. Price undercutting has been disclosed with respect to only one country the USA, which is negative. Price underselling has not been provided. Costing information in formats A, B, C-1, C-II and D has been kept as blank.
- iii. The sales price information which is available in public domain is also claimed confidential

### Examination by the Authority

23. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied with regard to claim on confidentiality, the same has been allowed. The Authority notes that the claim of confidentiality in the application in the present case is consistent with the practice being followed by the Authority. The interested parties have not established any specific instances of incorrect claim of confidentiality. The Authority has allowed claims of confidentiality with regard to information which is by nature confidential, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information. The Authority has required interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries.

### ASSESSMENT OF DUMPING— Methodology and Parameters:-

#### Normal Value, Export Price and Dumping Margin

#### Views of the Domestic Industry

24. Domestic industry has made the following submissions with regard to dumping:

- i. In the original investigation, the Designated Authority has constructed the normal value for exporters/producers from the subject countries based on facts available as per Rule 6(8) of the AD Rules. In the first sunset review investigation, the Authority has considered the information provided by the domestic industry in the application for determination of normal value for the subject countries based on facts available as per Rule 6 (8) and constructed the normal value.
- ii. In the present investigation, in spite of all reasonable efforts made by the Petitioners to procure the necessary information/evidence regarding the price of the subject goods in the domestic market of USA and

Japan when no evidence/information could be procured for the prevailing price of subject goods in the domestic market of the subject countries. In view of the same, Petitioners have determined the Normal Value in subject countries considering the constructed value approach.

- iii. The export price is calculated at the CIF level by comparing of normal value and export price at the same level of trade. Therefore, the export price has been adjusted for the various expenses that may have been incurred by the exporter for exporting the material to India.
- iv. The dumping margins for the subject countries in respect of subject goods as assessed are above the de-minimus limits and significant. Therefore, there is a strong likelihood of further exports coming at dumped prices in future.
- v. The domestic industry submits that the opposing party is not privy to the information relevant to determination of normal value and dumping margin and cannot be allowed to even argue the normal value and its determination.
- vi. The dumping of Aniline from the subject countries (especially USA) continued even after the imposition of anti-dumping duty. The continued dumping from the subject countries and the presence of such dumped materials in the market restrained the domestic industry to recover from the ill impact of the dumped imports from the subject countries.
- vii. During the post recession period there has been considerable increase in the volume of imports from European Union and there were low imports from USA, which is due to the fact that the major producers/exporters from the USA have their production facilities in European Union also. If the present duties be revoked, the imports would once again shift to USA. The only differential cost that would be involved is the incremental freight cost, which is negligible.
- viii. Further, merely because there is no dumping and so in a situation where there is no response from any of the producers/exporters from the subject countries, does not imply that there is no likelihood of recurrence and continuation of dumping in case of revocation of duty.

#### View of Exporters/Importers and Other Interested Parties

25. None of the exporters has responded in the present investigation. However, the importers have raised the following issues with regard to dumping:

- i. Normal value calculated by the domestic industry is highly inflated and is not based on any facts and principles. Some details of raw material as given by the petitioner are wrong. The petitioner has resorted to fiddling with information available even in public domain to mislead the Authority.
- ii. Exorbitant amounts towards freight, insurance and other charges to inflate the dumping margin.
- iii. There have been negligible imports from USA and no imports from Japan during the POI. In the matter of Flexible Slabstock Polyol from China PR, Korea RP, Chinese Taipei and Brazil, duties were struck down due to no imports from the subject countries.

- iv. There is no evidence produced by the petitioner in support of its claim of the dumping in the present matter. Petitioner has merely made assumptions.
- v. Normal value has been calculated on the basis of the cost of benzene and power as well as other adjustments based on prices and costs in the USA for both Japan and USA. The rates of benzene relied upon by the petitioner for the calculation of normal value is incorrect as the domestic market conditions and prices of these countries are not known.
- vi. No source has been provided for calculation of cost for other utilities than power, depreciation, and manufacturing expenses. There is no reliable source for the determination of normal value for Japan. Also, the cost so calculated based on the cost of US is untenable.
- vii. As from UNCOMTRADE it can be seen that there are no exports from Japan. Constructing the export price for Japan is against the law. Export price calculated for Japan by taking a weighted average price of all imports into India are erroneous and unjustified.
- viii. Methodology adopted for constructing export price of the PUC for Japan is baseless as the weighted average of all imports of the product under consideration into India cannot be relied upon for determining export price from Japan. Further, no source for the adjustments claimed for the export price has been provided.

### Examination By The Authority

26. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
  - a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
  - b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

27. With regard to the arguments raised by the interested parties on normal value and dumping margin determined in the application, the Authority holds that the claim of normal value in the petition is only one of the information at the

disposal of the Authority for determination of normal value. The Authority sought information from concerned foreign producers who have not responded in the form and manner prescribed. It is also noted that none of the responding importers, consumers or other interested parties have provided any information whatsoever for assessment of normal value, export price, dumping margin or any elements thereof. Under the circumstance, when exporters have preferred non-cooperation, the Authority is required to determine normal value on the basis of best available information. The Authority clarifies that the Authority has not merely followed the claims made by the petitioner and the Authority has made its own determination with regard to normal value, export price and dumping margin.

### Dumping Margin:

### Normal Value

28. The Authority notes that none of the exporters from the subject countries has responded to the initiation of the investigation and filed any information/response. As information about the actual domestic sales price, information on exports to third countries or cost of production in the subject countries and other information as per the questionnaire have not been furnished by any of the producers/exporters from the subject countries, the Authority determined normal value as per the best available information. The Authority notes that benzene is the major raw material for production of the product concerned. Normal value is determined considering prices of benzene in US region as per ICISLOR and consumption norms of the domestic industry. Petitioner has claimed that there has been very significant variation in the price of product concerned and material exported from the subject countries has not been exported in all the months of the period of investigation. Therefore, the Authority concludes that comparison of normal value and export price should be done on month to month basis. The Authority has, accordingly, determined separate normal value for each month in which material has been exported to India. Accordingly, weighted average normal value is determined as USD \*\*\* per KG.

### Export Price

29. As stated above, none of the exporters and producers has responded and furnished any information. Export price is, therefore, determined based on the imports information furnished by the DGCIS. The Authority notes that material has been exported from the USA in May 2010, June 2010 and Sept 2010. The Authority has determined separate export price month wise. Adjustments are made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank commission and inland freight and have been allowed. Accordingly, weighted average net export price of the three months comes to USD \*\*\* per KG.

30. With regard to Japan, the Authority had sent questionnaires to all the known exporters/producers for the purpose of determination of dumping margin. None of the exporters / producers from Japan filed submissions and response to the questionnaire in the form and manner prescribed. Article 6.8 of the Agreement provides that in case an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary or final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Since there were no exports of the subject goods from Japan during the POI, the current dumping margin could not be determined.

### Dumping Margin Calculations

USD per KG	USA
Normal value (US\$)	***
Export price (US\$)	***
Dumping margin (US\$)	***
Dumping Margin %	5-10 %

### LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

31. In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority considered the following parameters:-

- Dumping margin determined in the original investigation.
- Dumping margin determined in the present investigation – wherever exports to India existed during the investigation period, the same were considered and dumping margin determined. Wherever there were no exports to India during the investigation period, the dumping margins assessed in the original investigation is considered.
- Freely disposable present and potential capacities, considering known expansions undertaken by the foreign producers, prices prevailing in India, actual and potential volume of exports, export price from these countries to other countries.

32. On examination of these factors, the Authority concludes that:

- (a) Dumping margins are positive in case of exports from the USA;

(b) Export price from the USA is below the normal value;

(c) Landed value of USA exports is well above the net sales realization and the non-injurious price determined in the POI;

(d) The Authority also compared the landed values for exports from USA to other countries and notes that the same is not only higher than the NSR and NIP of the domestic industry but also higher as compared to landed value in India.

(e) The Authority notes that the likelihood test is required to be taken into account while determining revocation of anti dumping duty. In this regard, the Authority concludes that just because there is no response from the exporters from USA, it cannot be determined that withdrawal of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping from the USA. Further, no credible evidence was provided by the Domestic Industry in this respect.

33. As regards Japan, the Authority concludes that the domestic industry has not provided positive evidence that there is likelihood of dumping and consequent injury in case of cessation of anti-dumping duties. Available information with the Authority with regard to exports from Japan to third countries also does not suggest any likelihood of dumping and injury in case of cessation of anti-dumping duties. In this regard, as per the available information before the Authority, the capacity in Japan is 3,98,000 MT and actual production is 2,79,000 MT. But despite the surplus, there is no export or import of the subject goods from Japan to third countries in 2010, thus, showing no real possibility of diversion in case of revocation of duties.

### **ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK**

#### **Views of the Domestic Industry**

34. The following are the views of the domestic industry with respect to the Injury and Causal Link:-

- i. Imports of the product under consideration have continued from the subject countries. In fact, the volumes have remained significant and are undercutting the prices of the domestic industry in the market;
- ii. Landed price of imports are below the non injurious price of the product under consideration;
- iii. The domestic industry has not been able to improve its market share to the extent it could in the absence of dumped imports.

- iv. Production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry has remained low, despite the increase in demand due to presence of dumped imports in the Country. The sales of the domestic industry have declined in comparison to the base year due to the continued dumping of the subject product. Despite rising demand of the subject goods in India, the Domestic Industry was not able to optimize and improve its production and sales and utilize its capacity to its fullest extent.
- v. Even when the performance of the domestic industry has improved in terms of profitability and return on investment, the same is due to imposition of anti-dumping duties. However, profits before tax, profit before interest and profit before interest & depreciation remained low over the injury period when compared with the performance of the domestic industry in the year 2006-07. Further, performance of the domestic industry could improve further, but for the dumped imports in the market. The performance of the domestic industry continued to be adverse and was thus fragile. The volume of dumped imports from the subject countries has remained significant even after the applicable anti-dumping duty.
- vi. In spite of substantial increase in indigenous demand in comparison to the base year, the sales of the domestic industry could not reach to a satisfactory level rather declined in the period of investigation.
- vii. The volume of imports and consequently the market share of the subject countries have remained significant over the injury period. The possible decline in imports and consequent market share from the subject countries is due to the applicable anti-dumping measures.
- viii. Aniline is a 'commodity product'. In order to maintain their market, producers in USA or Japan will have to maintain the prices at the levels matching with that of Europe, which is significantly undercutting the prices of the domestic industry.
- ix. If injury information is segregated for HOCL and GNFC, it will show that Profitability of GNFC alone was much higher in 2006-07 and lower in period of investigation. Further, the volumes produced by GNFC were higher in 2006-07 as compared to period of investigation. If injury to domestic industry was on account of other factors, GNFC volumes would not have declined and its profits would not have deteriorated. Efficiency of HOCL has remained the same throughout the period. Such being the case, the issue unaddressed by the interested parties is why production of HOCL declined from above 7000 MT to about 2600 MT and why its losses have almost doubled over the years.
- x. HOCL production and sales volumes declined substantially and its losses increased significantly. Efficiency of HOCL has remained the same throughout the period. Such being the case, the issue unaddressed by the interested parties is why production of HOCL declined from above 7000 MT to about 2600 MT and why its losses have almost doubled over the years..
- xi. Allegation of including HOCL to inflate injury is baseless as the Designated Authority is required to examine injury to the "domestic industry" and not injury to individual constituents of the domestic industry.
- xii. The argument of the interested parties is baseless that there is increase in interest cost of the petitioner. Interest cost is adjusted by the Authority while determining the non injurious price.

- xiii. With regard to the allegation that the movement in benzene price has affected the aniline performance, Domestic Industry submits that there has been movement in benzene price not only in India but also in international market.
- xiv. Authorization letter for representing HOCL by TPM has been filed with the Authorities and is on record of the Authority. Merely because authorization is not in the public file, does not mean that the company is being represented without any proper authorization. Further, there is no confirmation by the representative of the Authority during the oral hearing, statement made by and on behalf of the Authority are misunderstood by the opposing parties.
- xv. It is alleged that HOCL stay away from production due to higher cost of captive raw material, higher labour cost and fixed cost. In this regard, domestic industry submits that the comparison of higher or lower is being done with reference to other producer of Aniline, which itself is incorrect.
- xvi. The Designated Authority should consider the domestic industry as it exists and not under ideal conditions. Notwithstanding, as informed at the time of spot verification, the company had been making efforts in reducing cost of production of hydrogen. The company has since been able to start producing hydrogen from natural gas, as was seen at the time of verification visit. With the production of hydrogen through natural gas, the cost of production of hydrogen for the company has substantially declined.
- xvii. GNFC is getting its major input captively from other plant of the company. The transfer price of this captive input is neither market price nor full cost. As opposed to this, HOCL is buying all the inputs, barring Hydrogen. Therefore, the injury to the domestic industry is distorted because of incorrect valuation of captive inputs. Since the captive input in case of GNFC is a very low value product otherwise to the company, its transfer price is totally unrealistic compared to market price. Resultantly, cost data of GNFC does not reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration.
- xviii. The present case clearly establishes that consideration of captive input at value other than market value can significantly distort the injury analysis and lead to discrimination between integrated and non integrated producers to the peril of those producers who are not backward integrated. It will lead to a situation where stand alone producer of Aniline in this case and other products in general shall not survive in the market. It shall also imply that no company would be able to produce (and make profits) Aniline and other products in the country until and unless it has its own captive input at a price much less than market value of such captive input.
- xix. Higher cost of captive inputs, higher labour and fixed cost is due to lower production, which is due to dumping of Aniline in India. There has been consistent increase in imports volume which forced the domestic industry to curtail production to avoid high inventories.
- xx. Intentionally, opposing parties have ignored vital facts that there has been very significant variation in Benzene price, which has consequent impact upon the cost and price of product. Such being the case, this would be misleading to compare one single cost and price for the whole year. If the same is compared on month to month basis, the undercutting and underselling would be positive.
- xxi. Even when the present investigation is in respect of USA and Japan, the Domestic Industry is suffering from dumping from other source i.e. EU and the

investigation is in progress. Imports from EU are at dumping prices and causing injury. The Designated Authority should cumulatively assess injury to the domestic industry. AD Rules specify for cumulative assessment when the Designated Authority finds that the conditions precedent are met. Petitioners therefore submit that cumulative assessment of injury to the domestic industry from dumped sources under simultaneous and separate investigations is not only desirable but also must.

35. The various parameters relating to domestic industry collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury.

#### **Views of the Exporters, Importers and Other Interested Parties**

36. The following are the views of the exporters, importers and other interested parties with regard to the injury to the domestic industry:

- i. HOCL has lost the opportunity to participate after the expiry of 40 days of the initiation. It is an inefficient component of the domestic industry which has shown inflated damage to the domestic industry, which is not shown by data of GNFC. Petitioner has tried to inflate injury by changing the injury figures substantially.
- ii. Over the entire injury period, the market share of HOCL remained as low as 10%, which cannot be attributed to imports.
- iii. The comparison of trends of both the participating companies is opposite. The GNFC has 107% capacity utilization whereas HOCL had 22% -27% of capacity utilization.
- iv. HOCL is not a regular producer due to internal reasons. HOCL produced PUC very sporadically during the year and such significant production was made at an irregular quantity and period of time scattered over a very few months in a year.
- v. The profitability of HOCL is negative whereas that of the GNFC is positive. Sales volume of HOCL is just 13% of the total domestic sales. The inclusion of HOCL has absorbed the entire profits of GNFC. This shows that the cost for the production of PUC to HOCL is highly abnormal.
- vi. The capacity utilization of HOCL has never risen more than 35-40% over the recent years, inclusion of HOCL would show inaccurate depiction of injury. The minor drop is due to economic slowdown and high stock by the petitioner.
- vii. HOCL was not operating on continuous basis due to its own internal problems. HOCL has not increased the market share in the domestic market, in spite of the fact that the landed price of imports was much above the domestic selling price. This clearly established that the injury to HOCL is self inflicted.
- viii. If dumping is the only reason for affecting the domestic performance, then the trends for performance for the participating companies must be same. The heavy losses of HOCL are on account of factors other than dumping.
- ix. Petitioner has tried to inflate injury by taking 2006-07 as the base year for injury analysis, thereby changing the indexed figures substantially.
- x. The information available in public domain, like annual reports, directors report etc clearly lacks reference to the issues concerning the dumping which has affected the aniline operations.

- xi. While determining the volume effect, the surge in imports is required to be seen and in the instant case there are no imports from Japan and there is no abnormal surge of imports from USA. There is no co-relation between injury and dumped imports.
- xii. In spite of no imports in the year 2009-10, there is a downward trend in the domestic selling price. Therefore, it is cost of sales and not landed value of imports from subject industries which are the influencing factor on domestic selling prices of Domestic Industry.
- xiii. No price undercutting and no underselling are present there.
- xiv. No NIP is provided by the petitioner.
- xv. Imports have declined considerably in spite of increase in demand. There is no decline in the market share of the domestic industry.
- xvi. Higher cost of captive production of inputs, higher labour costs, higher fixed cost due to low capacity utilization, and high incidence of cost on plant closures made it not to produce the PUC.
- xvii. Sales quantities have increased except for 2008-09 which was due to fall in capacity utilization caused by plant shutdown and economic slowdown.
- xviii. The losses to the domestic industry are due to the decline in export sales. The decline in sales is only due to the lower production value. The sales production ratio has been consistent over the injury period.
- xix. The annual report of 2008-09 of the petitioner mentions that production was adjusted to maximize profit and have not attributed any losses to dumping.
- xx. The GNFC operated through traders and therefore, the actual price to be considered is much higher than the price of GNFC whereby injury (if any) is further reduced. No information has been provided with respect to the traders.
- xxi. It is observed that the operating profit, return on capital (NFA) of the petitioner has risen dramatically over the period of investigation. Thereby concluding no injury to the domestic industry.
- xxii. The petitioner has claimed injury even in the year 2009-10, without any imports from the subject countries. Therefore injury suffered then is not on account of the alleged imports, rather attributable to other factors.
- xxiii. There has been sudden rise in the interest rates of the domestic industry since 2007-2008. There has been no expansion by the domestic industry. Therefore the source of interest expense ought to be verified. PBIT, selling price and sales value have increased over past years, price undercutting has been negative for all four years, which shows that the rise in interest rate is one of the chief causes for the perceived losses suffered by the domestic industry.
- xxiv. The losses are due to the poor off take of the downstream products as has been stated in the annual report of 2008-09, which has led to an unstable market situation for Aniline.
- xxv. The prices of benzene have affected the prices of aniline more than the imports. Prices of benzene have remained unstable for the period of injury.
- xxvi. No causal link between injuries suffered by Domestic Industry, if any, and alleged dumped imports. The absence of any significant volume of imports from subject countries for such prolonged period along with negative price undercutting and huge profits of the domestic industry rules out any causal link and also likelihood of recurrence of dumping in the event of revocation of duties.

xxvii. There has to be an existence of reasonable identical circumstances and period to cumulate countries and it cannot be done solely for the reason of having related parties to request for such cumulation which also is an erroneous fact. There are certain factors which are distinct in the parallel investigations such as (a) the nature of investigation (b) conditions of competition between both the markets per between both the markets per between both the subject countries (c) POI though overlapping have different periods.

### Examination by the Authority

37. With regard to submissions on injury by opposing interested parties, the Authority has critically examined the submissions made by the interested parties and has made the present determination. Further, the Authority notes as follows:

- a) With regard to the inclusion of HOCL for the purpose of determination of injury, the position has been examined. The Authority concludes that it is factually incorrect that capacity utilization of HOCL has remained all along quite low. In fact, HOCL had achieved almost 100% capacity utilization in 1997-98. Despite the same, operational and technical situation being faced by the company at that time and at present, its capacity utilization has significantly declined. The Authority concludes that it is incorrect that HOCL is not a regular producer of Aniline. The company has suspended production of Aniline whenever faced with significantly high inventories.
- b) The Authority further notes that the injury information of GNFC shows that the performance of the company has improved. However, the profitability of the company is below reasonable level.
- c) The Authority notes that with regard to the arguments of injury in 2009-10 despite no imports, the domestic industry claimed that there are significant imports of the product from European Union in this period, which are allegedly at dumped prices and the investigations are being conducted at present. The domestic industry also argued that merely because the present Sunset Review investigation is in respect of Japan and the USA, it does not imply that the impact of dumped imports from European Union should be completely ignored, particularly while assessing performance of the domestic industry. The domestic industry also argued in this regard that the Rules provide for assessing consequent impact of "dumped imports" on the domestic industry. The Domestic Industry also argued that since imports from European Union are allegedly at dumped price, the consequent impact of dumped imports on domestic industry shall imply injury to the domestic industry from all the dumped imports. The Authority also notes that the present investigations are sunset review investigations and the Authority is required to determine continuation or likelihood of dumping and injury. The Authority has examined the contention of the domestic industry that the exports from European Union may be diverted from USA and come to India in case the duties are

withdrawn. The Authority examined these submissions and finds that the same are mere apprehensions. The fact that some of the producers have their plants in EU and USA does not establish their case that the imports from EU would be diverted to USA as the incidence of freight would be higher in case of USA and the price of subject goods from USA would in all circumstances remain higher. The domestic industry also failed to provide cogent evidence on record in support of their claim. Therefore, in the absence of any material evidence from the domestic industry and based on the facts available, the Authority does not find any merit in this submissions of the domestic industry.

- d) With regard to the arguments that petition does not contain information on non injurious price or price underselling, the Authority notes that there is no such legal obligation on the domestic industry. In fact, the non injurious price or price underselling is required to be determined by the Designated Authority. The interested parties are being given opportunity to comment on the same through the present disclosure statement.
- e) With regard to higher cost of production of HOCL due to a number of factors identified by the interested parties, the Authority notes that actual cost of production of HOCL has not been adopted for present purpose. In fact, the non injurious price of the domestic industry has been determined by considering 100% capacity utilization of HOCL to remove injury, if any, due to other factors. Thus, it cannot be argued that cost of production of HOCL could be higher because of loss of production and higher incidence of various costs. Comparison of consumption norms of HOCL and GNFC shows that the raw materials consumption norms of HOCL are quite comparable to GNFC.
- f) It is clarified that the Authority has not adopted the claim of cost of production and various expenses charged to the cost of production by HOCL. The Authority has scrutinized the cost of production of domestic industry in detail and has adopted expenses only after sufficient scrutiny.

38. The Authority notes that it has been argued that HOCL is not producing regularly and the company should be excluded from the scope of the domestic industry. The Authority has verified the premises of the company and its records. It has been noted that there is no technical constraints for production of Aniline. The company claimed that the only constraint is sales as the customers demand matching prices of dumped material. Whenever the company suspended production, the Authority notes that inventory levels were high. It is noted that in April 2011, inventories reached to 1227 MT. Still company produced the product concerned in May 2011 and maintained inventory. However, the company claimed that the company cannot produce just to create inventory in a situation of unremunerative prices. The Authority further examined whether operation of the HOCL can be viable. In this regard, the Authority notes that dumping of Aniline has caused injury to HOCL and company is trying to recover from dumping. Company has claimed that even in the period of investigation, contribution of the company has been positive, and at 80% capacity utilization levels, there would be significant positive contribution. The Authority further notes that cost of GNFC on account of hydrogen is not reflective of the cost of production of hydrogen. GNFC

produces hydrogen from waste gas and charges only opportunity cost to hydrogen cost. GNFC claimed that if correct cost is charged to hydrogen, cost of hydrogen would be significantly higher.

### Volume Effect of Dumped Imports

39. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping Rules provides as under:

*"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"*

### Assessment of demand and market share

40. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed can also be seen in the table mentioned below:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Demand	MT	65,082	47,636	63,233	72,275
Sales of Domestic industry	MT	43,388	33,562	39,045	41,053
Sales of Other Indian Producers	MT	3000	5200	5200	5200
Imports – all sources	MT	18,694	8,874	18,987	26,022
<b>Market Share in Demand</b>					
Domestic industry	%	66.67%	70.46%	61.75%	56.80%
Other Indian Producers	%	4.61%	10.92%	8.22%	7.19%
Subject Countries	%	9.33%	0.00%	0.00%	5.33%
Imports from European Union	%	2.80%	18.63%	29.99%	30.58%
Other Countries	%	16.59%	-0.00%	0.04%	0.09%

41. The Authority notes the following from the above-mentioned table:

- i. It would be seen that there has been an overall increase in demand of the product in the country over the injury period including the period of investigation.
- ii. The volume of imports from the subject countries which stopped after base year started again in the period of investigation and reached to a significant level.
- iii. Sales of the domestic industry have declined in 2008-09, which increased in 2009-10 and period of investigation, however, still remained lower than base year.
- iv. Further, market share of domestic industry increased in 2008-09, declined in 2009-10 and further declined in period of investigation.

#### Import volumes and market share

42. The actual volume of imports during the period of investigation has been as under:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Imports from USA	MT	5,978	-	-	3,852
Imports from Japan	MT	96	-	-	-
Imports from Subject Countries	MT	6074	-	-	3,852
Imports from European Union	MT	1,821	8,874	18,964	22,104
Imports from Other Countries	MT	10,799	-	23	65
Total Imports	MT	18,694	8,874	18,987	26,022
<b>Market Share in Imports</b>					
USA	%	31.98%	0.00%	0.00%	14.80%
Japan	%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
Subject Countries	%	32.49	-	-	14.80
European Union	%	9.74%	100.00%	99.88%	84.95%
Other Countries	%	57.77%	0.00%	0.12%	0.25%
<b>Market share in Demand</b>					
Domestic industry	%	66.67%	70.46%	61.75%	56.80%
Other Indian Producers	%	4.61%	10.92%	8.22%	7.19%
Subject Countries	%	9.33%	0.00%	0.00%	5.33%
Imports from European Union	%	2.80%	18.63%	29.99%	30.58%

Other Countries	%	16.59%	0.00%	0.04%	0.09%
-----------------	---	--------	-------	-------	-------

43. The Authority notes the following from the above table:

- i. The demand for the subject goods has shown a positive trend and increased.
- ii. The volume of imports and consequently the market share of the USA have declined, though remained significant. Though, nil imports were reported from USA in the year 2008-09 and 2009-10, the volume of imports increased significantly in the period of investigation.
- iii. The volume of imports recorded from Japan is minimal in base year and stopped subsequently.
- iv. Considering that the present investigations are sunset review investigations, the Authority hold that imports from USA continue to hold significant share in the Indian demand.

#### Price Effect

44. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows"

*"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."*

45. The Authority notes that in a review investigation, it is required to examine whether there has been a significant price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether there is likelihood of recurrence of price effect after cessation of duty. The Authority further determined whether the domestic industry is likely to face price underselling in the event of expiry of anti-dumping duty.

46. The Authority notes that the landed price of imports is higher than the selling price of the domestic industry as is evident from the table below:

Particulars	Unit	May 2010	June 2010	Sept 2010	AVG
Landed Price	Rs./MT	***	***	***	***
Selling Price of Domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***

Indexed	Rs./MT	100	97	92	96
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Indexed	Range%	0-10	(0-10)	(0-10)	(0-10)

47. The Authority further notes that difference in landed price of imports and selling price of domestic industry is very insignificant, which shows that the dumped material is competing with the domestic industry. The Authority further notes that out of the 3 months in which material are imported, price undercutting is positive in one month. However, in average the price undercutting is Negative.

#### Price suppression and depression

48. Price depression exists when the prices of the domestic industry decline over the injury period with the import prices remaining lower than the domestic industry's prices. Price suppression occurs when the dumping prevents price increases that would otherwise take place due to increase in costs.

49. The Authority has examined whether there was a significant adverse price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	Oct.09-Sept.10
Cost of production	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	112	107	102
Net sales realization	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	106	99	109

50. The Authority notes that the cost of production of the domestic industry increased in 2008-09 and declined thereafter. At the same time, the selling price increased in 2008-09; declined in 2009-10; and again increased in the period of investigation. The Authority further notes that till 2009-10, domestic industry incurred financial losses and made profits in the period of investigation. In view of the above, the Authority concludes that there is no price depression and suppression in the period of investigation.

#### Other Economic Parameters relating to the Domestic Industry

51. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on

domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down as follows"

*"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

### Production, Capacity and Capacity Utilization, Sales

52. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	P O I
Capacity	MT	60,100	60,100	60,100	60,100
Production	MT	44,981	33,900	39,386	40,040
Sales	MT	43,388	33,562	39,045	41,053
Capacity Utilization	%	75%	56%	66%	67%
Demand	MT	65,082	47,636	63,233	72,275
Market Share of Domestic industry	%	66.67%	70.46%	61.75%	56.80%

53. The Authority notes the following:

- i. The production and capacity utilization of the domestic industry declined in comparison with the base year in spite of significant increase in demand over the injury period.
- ii. Production increased in period of investigation. However, it remained at a lower level compared to the base year.
- iii. Sales also show the same trend as of production.
- iv. At the same time, demand shows positive trend all along, and resultantly, domestic industry lost market share.

### Profits, return on investment and cash flow

54. Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as under:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	P O I
Profit before interest and tax	Rs./Lacs	***	***	***	***
Indexed		(100)	(204)	(286)	81

Return on capital employed	%	***	***	***	***
Indexed		(100)	(220)	(460)	120
Cash profit	Rs./MT	***	***	***	***
Indexed		(100)	(355)	(484)	215

55. The Authority notes that the profitability of domestic industry which deteriorated till 2009-10, improved in the period of investigation. Similar trend is observed with respect to cash profit and return on investment as well. It has been claimed by the interested parties that HOCL should be excluded from the scope and there are other factors of injury to the domestic industry. Though, authority does not find any merits in the argument, however, the Authority examined the performance of GNFC separately and noted that performance of GNFC is better than that of HOCL. At the same time, it is noted that GNFC is not charging Hydrogen cost to Aniline on cost basis and the same is being charged on opportunity cost basis, which is significantly lower than the normal cost of production. If Hydrogen is charged to Aniline on cost, return on capital employed of the company would decline significantly compared to the present levels. However, the Authority has determined injury to the domestic industry as it exists and profitability is determined as per records maintained by each constituents of the domestic industry.

### Employment and wages

56. The Authority notes that the constituents of the domestic industry are multi-product companies and, therefore, there may not be direct effect of dumping on employment levels of the domestic industry. Status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	P O I
Employee	NO	***	***	***	***
Wages	Rs./Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	113	145	142

57. The Authority notes from the above that there is a slight decline in the level of employment over the injury period. Wages paid have shown normal wage growth.

### Actual and potential decline in Productivity

58. The productivity of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	P O I
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Indexed		100	76	88	89
Productivity per employee	MT/No	***	***	***	***

59. The Authority notes from above table that productivity per employee of the domestic industry has shown slight improvement in the P O I as compared to the previous year. However, the same declined compared to the base year.

### Inventories

60. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	P O I
Average Stock	MT	***	***	***	***
Average Stock sufficient for no of days sales	Days	***	***	***	***

61. Based on the above, the Authority notes that the inventory levels of the domestic industry have significantly increased over the injury period including the P O I and that despite increase in demand, inventory which was just equal to 5 days sales in the base year, increased significantly to 20 days sales.

### Growth

62. On examination of various economic parameters of the domestic industry, the Authority notes that the production and sales declined compared to base year, domestic industry lost market share, profitability of the domestic industry improved, but still remained below the legitimate levels, and the inventory increased significantly. Overall, growth of the domestic industry remained negative. The Authority further notes that the adverse effect on growth, if any is due to the increase in imports from European Union but not from the imports from subject countries as the imports from them are well above the net sales realization and non-injurious price of the domestic industry.

### Ability to raise capital

63. The domestic industry is a multi product company. Their ability to raise further investment is not a significant factor in this case. However, should the dumping from the present sources persist, ability of the domestic industry to raise capital would suffer severely.

### **Magnitude of Dumping**

64. It is noted that the dumping margin from the USA is positive. However, in view of no imports of subject goods from Japan during the period of investigation; dumping margin could not be calculated for Japan.

### **Factors affecting Domestic Prices**

65. Change in the cost structure, if any, and competition in the domestic industry, have been examined for analyzing the factors other than the dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. The Authority notes that with the anti-dumping duty in place, there are no external factors affecting the prices of the domestic industry during the injury period of this review investigation.

### **Other Known Factors:**

#### **Volume and Prices of imports from Other Sources**

66. The Authority notes that during the POI, imports have taken place from the subject countries in the present investigation, and from other countries against which investigation is in progress. Imports from countries other than the subject countries are insignificant, and therefore, could not have caused injury to the domestic industry.

#### **Contraction in demand and / or change in pattern of consumption**

67. The Authority notes that the demand of the subject goods has registered a positive growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to injury to the domestic industry.

#### **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

68. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The domestic industry competes among one another and at the same time competes with the landed price of the subject goods. The price of the domestic industry is determined by the landed price of subject goods. Moreover, imports from other sources have sizable presence in the Indian market.

#### **Development of technology and export performance**

69. The Authority notes that technology or technology related issues have not been raised by any interested party as a cause of injury to the domestic industry. Further, the technology as also production process for producing subject goods is fairly stabilized with little technical or technological developments. There is no known difference between the technology employed by the petitioner and producers in subject countries.

## Exports by the domestic industry

70. The Authority notes that the exports of the domestic industry have declined. However, domestic industry furnished all information segregated for domestic operations. Therefore, the above grave injury is caused only by dumping.

## Likelihood of Continuation / Recurrence of Dumping

71. Following submissions are made by the domestic industry with respect to the likelihood of continuation/recurrence of dumping:

- i. The likelihood determination is a prospective determination and the Authority must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty is terminated.
- ii. Improvement in the present performance is due to anti dumping duty in force and in such a case, the Designated Authority is required to examine the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. In case, the Designated Authority holds that there is no continued injury to the Domestic Industry, the likelihood of injury to the domestic industry is required to be seen in the event of expiry of the anti dumping duty in force.
- iii. The exporters and producers from the subject countries continued to export the material at dumped prices even after the imposition of the dumping duty. The market share of the imports from the subject countries was low but significant because the very same foreign producers were able to sell the product from EU. Situation of the domestic industry deteriorated in terms of production, sales, capacity utilization, and market share. The domestic industry is thus suffering adverse volume effect and continued injury.
- iv. If the domestic industry has not suffered injury from Japan in the event of no imports from Japan, it is required to examine whether the cessation of the anti dumping duty in force would result in the recurrence of dumping. Since, producers and exporters from the subject countries are quite aggressive in exporting the subject good to the Indian market, the examination of recurrence of injury is very important.
- v. The level of current dumping is very significant. This alone establishes the need for continuation of anti-dumping duty.
- vi. USA is exporting the subject goods to third countries at significant dumped prices, and if the applicable anti-dumping duty is allowed to cease, USA would surely intensify dumping of subject goods into India.
- vii. The prices prevailing in Indian market are quite attractive for the foreign producers. USA is exporting the subject goods to third countries at the prices far below than the selling price offered by the Domestic Industry. It is due to the applicable duty on USA and no anti dumping duty on Europe, that the US producers are not exporting significant volumes.
- viii. If current duties are allowed to cease in the present case, USA will not only increase the dumping of subject goods but will also maintain the prices matching with that of Europe.

- ix. Subject countries hold excessive capacities when compared with demand. Thus, exporters/producers from the subject countries have the potential to raise dumped exports to India.
- x. The production, domestic sales, capacity utilization and market share of the domestic industry declined. In view of significant unutilized capacities with the subject exporters and significant demand of the product in the Indian market should the current duty not be continued further, the imports shall increase substantially and sales of the domestic industry would further decline. Considering the price sensitivity of the concerned product, subject imports would increase substantially in the event of cessation of anti-dumping duties.
- xi. The situation of the domestic industry continues to be fragile. Cessation of current anti dumping duties is likely to lead to injury to the domestic industry in respect of the product under consideration.
- xii. Tribunal has held in a number of cases that the dumping would cause injury if the price undercutting without prevailing anti dumping duties is positive; if the price undercutting from a particular country is negative, if the imports are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry and if the landed price of imports is below not only selling price of the domestic industry but also non injurious price of the domestic industry.

#### View of Exporters/Importers and Other Interested Parties

72. The following are the views of the exporters, importers and any other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury:

- i. Claim of likelihood and recurrence of injury is based on mere conjectures. Excess capacity and price attractiveness of Indian Industry without any evidence.
- ii. Imports from Japan were almost none during last 10 years, which clearly shows the paradigm shift in the nature of imports from Japan that of a long lasting nature ruling out any likelihood of recurrence of dumping.
- iii. Third country exports from Japan is also either nil or of insignificant quantity. Japan has become a net importer of Aniline and the demand in the country has led to more and more exports being curtailed.
- iv. The claim of the petitioner that USA has been exporting the subject goods to third countries at significant dumped prices, is unsupported by any real evidence.
- v. Assuming the subject goods from USA to land in India at prices at which it exports to world and China, the price undercutting will be negative. To match DI's NSR, USA has to offer a very low price which is beyond possibility when they are exporting the material at a very high price to third countries. Therefore Indian market is not attractive to for USA.
- vi. Out of 77000 MT exported by USA only 2000 Mt (less than 3% of total exports) has been exported to India and that too at a price higher than the NSR. 60000 MT has been exported to China, being a more attractive market.
- vii. The statements that the exports from USA are shifted to EU and that might again switch to US are far from reality. These are merely to mislead the Authorities.

- viii. No evidence has been provided to show the existence of relationship of producers of Europe and USA/Japan. There is only one producer who has a plant in both the jurisdiction.
- ix. No mention of the source of information claiming surplus global capacities leading one to doubt the authenticity of the figures in the table.

### Examination by the Authority

73. The Authority, with regard to the post Disclosure Statement submissions relating to likelihood of dumping and injury, notes that as regards USA, there are imports of the product under consideration in the POI. Petitioners claimed that there is freely disposable capacity of 1,90,000 MT in USA which is sufficient to eat up the entire Indian demand. The Authority has considered the report by Merchant Research & Consulting Ltd. relating to surplus capacity in USA. The surplus capacity in USA in 2010 is determined by taking total capacity reduced by the demand in USA and the exports by USA to all countries including India. The surplus capacity calculated as per the said report is 97,037 MT. However the domestic industry has not established as to how the same would find way into the Indian market at a lower price when they are already getting a higher price than the NSR and NIP of the domestic industry. Further, USA is realizing even higher price in foreign markets other than the Indian market. The objective of a business is to earn and maximize profits but not to incur or increase losses. The fact of mere availability of surplus capacity does not in itself sufficient to conclude a finding that the dumping from a subject country, USA in the present case, would recur or continue and cause injury to the domestic industry in case of withdrawal of duties. Further, there is no rationale in the submissions of the domestic industry that when European Union is significantly undercutting the prices of the domestic industry, USA would also export at the same level of prices causing undercutting compelling the domestic industry to reduce its prices.

74. Further, the injury to the domestic industry, if any, is there because of imports from European Union as the imports from European Union have increased significantly in POI. There is no injury from the imports from subject countries nor there is any likelihood of injury from import from the subject countries.

### Magnitude of Injury and injury margin

75. The non-injurious price for the subject good has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for the same description for determination of injury margin. The analysis is done on month to month basis. The Authority notes that landed price of imports is more than the non injurious price of domestic industry, which is as follows. However, the Authority notes that present investigation is a sunset review investigation and it is the consistent practice of the Authority to hold that NIP – NSR comparison has not much of relevance.

NIP (Rs. per kg)	***
------------------	-----

Landed Price (Rs per kg)	***
Injury Margin (Rs per Kg)	***
Injury Margin as % age of Landed Price	(5-15)%

**Post Disclosure Statement submissions of the domestic industry and the trader, importers, consumers and other interested parties**

76. The Authority has examined the post Disclosure Statement submissions of the domestic industry and the trader, importers, consumers and other interested parties. The Authority has dealt with them to the extent they are relevant to the present investigation, in the appropriate headings in the Final Findings. Some main issues raised by the importers/other interested parties are as under:

- a. It has already been established that HOCL should be excluded as injury to HOCL is due to other factors. Injury to HOCL has distorted the whole injury analysis.
- b. RTI reply given by HOCL shows that there was no piling of stocks.
- c. There is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Landed price of imports is higher than selling price and non injurious price of domestic industry. The US producers enjoy a better market in China. Therefore, there is no likelihood that they would dump the product to India.
- d. Petitioner has claimed surplus capacity based on 2006 figures in subject countries as well as the world by ignoring the facts relating to growth in demand.
- e. Petitioner is trying to give a bogus interpretation of global surplus situation and misleading the Authority by saying that such surplus will be diverted to Indian market in the event of revocation of duties. When there were no significant imports during the past 10 years from subject countries, chance of these countries preserving their capacity to fill the Indian market at dumped prices is nothing but a wild imagination.
- f. Anti Dumping investigations are country specific. Therefore, contention of domestic industry that the US producers would export to India at price levels of European Union is without any legal basis.
- g. Landed price is much higher than the selling price of the domestic industry.
- h. Post POI data in terms of volume should be analyzed.
- i. Price undercutting is negative. Landed price of imports is much higher than the selling price of the domestic industry and there is no price suppression and depression.
- j. Incorrect import data has been considered in the disclosure statement.
- k. Non participation alone is not sufficient to establish likelihood of recurrence of dumping and injury.
- l. Profits of domestic industry are above reasonable levels.
- m. The Indian importers have provided dumping margin calculation which shows that the dumping margin determined is negative.
- n. It is stated in the annual report of HOCL that Rasayani plant was under technical and maintenance shutdown in 2006-07.
- o. There is no proper non-attribution analysis, examining the injury due to other factors causing injury to HOCL.

- p. Statement relating to costing of Hydrogen in paragraph 19 is a generalized statements without any data to support or corroborate the claims made by the Authority and, therefore, leaving NOCIL deprived of sufficient information to make any comments on this issue.
- q. 13 years old production has been relied upon for examination of technical constraints of HOCL. This is clearly illegal, unprecedented and without the authority of law.
- r. Inclusion of HOCL into the domestic industry at this stage of the investigation is inconsistent with precedents and without the authority of law. There can be no justification for changing the constituents of the Domestic Industry at the whim and convenience of the petitioner.
- s. There is no requirement or justification to keep dumping margin calculation confidential. The information relied upon by the Authority to arrive at normal value and export price at ex-factory levels is not business proprietary information. Rather, it is the information from the public domain that ought to be disclosed. For instance, there is no justification to conceal export prices as per DGCI&S data under the garb of confidentiality.
- t. The inefficiency of HOCL with regard to production cost cannot be adjusted to increase NIP by taking capacity utilization at 100%. If anything, HOCL's inefficiency should be taken into account considering that the inefficiency has existed for several years now, irrespective of dumping and injury. Further, Annexure-III, post the recent amendment, is now clear on the calculation of NIP. All factors are to be taken at best utilization rates over the injury period and the period of investigation. At no point in the injury period or the period of investigation was the capacity utilization of HOCL anywhere near 100%.

77. The issues raised by the domestic industry are as under:

- a. Since the constructed normal value is based on information of the domestic industry, the same cannot be confidential from the domestic industry.
- b. There is calculation error in calculation of working capital, further certain debtors are disallowed which is incorrect, further while bad debts is not allowed as part of cost, provision of bad debts is not removed from working capital.
- c. Determination of normal value as per lowest NIP is inconsistent with the Rules and against the interest of domestic industry. While determination, abnormal cost of domestic industry is removed at the same time, abnormal benefit is not removed, providing undue benefit to exporter for their non cooperation.
- d. Domestic industry has collected data of exports from USA to world countries including India, China, EU etc. It may be seen that exports to China increased till 2010 declined significantly in 2011 – upto Oct period. Same data shows that exports to EU also increased and exports to India are lower price compared to other world markets.
- e. Down time report of HOCL for the injury period shows that production of Aniline plant of the company was suspended due to low off take, uneconomic market conditions and other factors as well. Analysis of which shows that even if effect of other factors is removed, production of HOCL declined significantly.

### **Examination by the Authority**

78. The issues raised by the Domestic Industry and the interested parties have been examined by the Authority hereunder:

- a. The issue relating to exclusion of HOCL has already been dealt with above in the appropriate head and the Authority does not find any new submissions from the interested parties and the same are repetitive in nature.
- b. The Authority notes that RTI reply given by HOCL was only in respect of one Aniline plant whereas the company has three Aniline plants. Thus, RTI reply for one plant cannot provide any meaningful guidance.
- c. With regard to use of import data, it is stated that the same has been obtained from DGCI&S and correctly used. Further, there is no anomaly in determining the dumping margin.
- d. The Authority does not find merit in the submissions of the interested parties with regard to disclosure of normal value and dumping margin as the same is based on confidential information provided by an interested party which cannot be disclosed to other interested parties.
- e. The Authority has determined the non-injurious price of HOCL in accordance with the provisions of Annexure III to the Anti-dumping Rules and as per the established practices. Further, the NIP of HOCL has been determined at 100% of capacity utilization to remove injury, if any, due to other factors.
- f. With regard to calculation error in NIP, the Authority has reviewed the calculation and calculation errors have been rectified wherever found necessary. With regard to disallowing certain current assets, the Authority has followed consistent practice, based on which certain assets are disallowed.
- g. With regard to down time report of HOCL, the same has been analysed by the Authority and the Authority notes that it is not going to change any injury analysis. Down time report filed by the opposing parties as well as the domestic industry clearly shows that HOCL plant has been under shutdown due to low off take and uneconomic market conditions in addition to other factors. The Authority has made detailed analysis of the same and noted that after even excluding effect of other factors, production, sales and capacity utilization of domestic industry shows decline trend.

### **Likelihood of dumping and injury:**

79. The Authority notes that the dumping margin is positive for USA in the POI. However, the landed value for USA is more than the net sales realization and

the non-injurious price of the domestic industry in the POI. The Authority has also computed the landed value for exports from USA to third countries and found that the same is even higher compared to the landed value for Indian market. It implies that the exports from other countries would not find their way into the Indian market. Further, imports from USA are made at a price significantly above the NSR and NIP of the domestic industry.

80. The Authority further examines the claims of the domestic industry that there is freely available disposable capacity of 1,90,000 MT in USA which is sufficient to eat up the entire Indian demand. As stated above, the Authority has considered the report by Merchant Research & Consulting Ltd. relating to surplus capacity in USA. The surplus capacity in USA in 2010 is determined by taking total capacity reduced by the demand in USA and the exports by USA to all countries including India. The surplus capacity as per the said report is 97,037 MT. However the domestic industry has not established as to how the same would find way into the Indian market at a lower price when they are already getting a higher price than the NSR and NIP of the domestic industry. Further, as stated above, USA is realizing even higher price in other markets than the Indian market. The objective of a business is to earn and maximize profits but not to incur or increase losses. The fact of mere availability of surplus capacity does not in itself sufficient to conclude a finding that the dumping from a subject country, USA in the present case, would recur or continue and cause injury to the domestic industry in case of withdrawal of duties. Further, there is no rationale in the submissions of the domestic industry that when European Union is significantly undercutting the prices of the domestic industry, USA would also export at the same level of prices causing undercutting compelling the domestic industry to reduce its prices.
81. The Authority also examined the contention of the domestic industry that the exports from European Union may be diverted from USA and come to India in case the duties are withdrawn. The Authority examined the submissions of the domestic industry and finds that the same are mere apprehensions. The fact that some of the producers have their plants in EU and USA does not establish their case that the imports from EU would be diverted to USA as the incidence of freight would be higher in case of USA and the price of subject goods from USA would in all circumstances remain higher. The domestic industry also failed to provide cogent evidence on record in support of their claim. Therefore, in the absence of any material evidence from the domestic industry and based on the facts available, the Authority does not find any merit in this submissions of the domestic industry.

82. In view of the above, it is concluded by the Authority that the imports from USA in all likelihood would not come at a price which would cause injury to the domestic industry in case of withdrawal of duties.

83. With respect to Japan, as noted above, there are no imports from Japan over the injury investigation period except negligible imports in 2007-08. Further, as per the available information before the Authority, the capacity in Japan is 3,98,000 MT and actual production is 2,79,000 MT. However, despite the surplus capacity in Japan, there are no exports by them to India and as well as to other countries. It indicates that the Indian market is not important for them and does not, show any real possibility of diversion in case of revocation of duties. Under such a situation, the Authority finds that there is no likelihood of recurrence of dumping from Japan and consequent injury to the domestic industry.

### Indian industry's interest and other issues

84. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

85. The Authority recognizes that the purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

### Conclusions

86. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the domestic industry and other interested parties and the facts available before the Authority as recorded in these Final Findings and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- (a) Aniline has been exported to India by the United States of America below its normal value resulting in positive dumping margin during the POI;
- (b) There are no imports from Japan in the injury investigation period except negligible imports in the base year 2007-08;
- (c) The domestic industry has not suffered any injury from the imports from the subject countries; and
- (d) There is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty imposed on imports of Aniline from the subject countries is withdrawn.

### **Recommendations**

- 87. Having concluded on the basis of information available on record that there is no likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury on account of imports of the subject goods from the subject countries based on the information on record if the duties are revoked, the Authority recommends for withdrawal of duties imposed on the subject countries vide Notification No 58/2006-Cus dated 9.6.2006.
- 88. An appeal against order of the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority